

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

प्रदेश में नक्सल हिंसा से मुक्ति कब तक

झीरमघाटी के समीप अरनपुर में 10 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों सहित 11 लोगों की शहादत ने एक बार फिर प्रदेश को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद माओवादी संगठन ने विज्ञप्ति जारी कर अपने इस कार्यान्वयन करतूत को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। उनका कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा नक्सलियों को 2024 तक समाप्त करने की रणनीति के खिलाफ उन्होंने इस हिंसा से अंजाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय माओवादी संगठन बना था और इसके बाद बदरत के स्थानीय लोगों ने सलवा जुद्ध शुरू किया था। माओवादी संगठन ने इसके विरुद्ध हिंसा शुरू कर दी थी। भाजपा शासन के 15 वर्षों में माओवादी हिंसा के चलते सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी संख्या में शहादत दी। कांग्रेस पार्टी के एक काफिले पर हमला कर तत्कालिन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, महेन्द्रकर्मा सहित 28 नेताओं की हत्या कर दी थी। झीरमघाटी का वह हत्या कांड आज भी वर्तमान सरकार की फाइल में जीवित है। इस कांड को लेकर राजनीति तो जमकर हो रही है लेकिन इसके अंजाम देने वाले माओवादी संगठन के खिलाफ कोई आक्रामक नीति नहीं बन पाई। आक्षेप की बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने जनघोषणा पत्र को झीरमघाटी के शहीदों को समर्पित किया था इसके साथ ही इस बात का संकल्प भी लिया था कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास किए जाएंगे। पिछले चार वर्षों में नक्सल समस्या के समाधान के लिए कोई नीति बनी हो ऐसा ध्यान में नहीं आता न ही वार्ता शुरू करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रयास आता है वह भी इस समस्या के समाधान की ओर गंभीरता से नहीं दर्शाता। शासन की ओर से ऐसा माना जा रहा कि चार वर्षों से माओवादी हिंसा नहीं हो रही है। केन्द्र सरकार भी कुछ ऐसा ही कह रही है कि देशभर में माओवादी हिंसा कम हुई है। प्रदेश में नक्सलियों ने बीते साढ़े चार वर्षों में अपनी रणनीति बदल दी है अब वे कोई बड़ा हमला करने के बजाय टारगेट किलिंग कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक बस्तर संभाग में बीते पांच सालों के दौरान 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं इनमें 335 ग्रामीण और 168 जवान शामिल हैं। हालांकि इसी दौरान 327 नक्सली भी मुठभेड़ों में मार गिराए गए हैं। सवाल यह कि प्रदेश सरकार बस्तर संभाग में छाई शांति का क्या मायने निकाल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शांति का लाभ उठाकर माओवादी संगठन अपना विस्तार कर रहे हैं। जब माओवाद के खिलाफ आक्रामक नहीं होगा तो फिर शांति तो बनी ही रहेगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से ही बेलाडोला की पहाड़ी हो या सिलेग में सुरक्षा बलों का कैंप खोलने का विरोध स्थानीय लोग सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सिलेग में आज भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस तरह की स्थानीय आंदोलन के पीछे माओवादी के सहभागिता से इंकार नहीं किया जा सकता। शासन को चाहिए कि माओवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए जिससे आगामी विधानसभा चुनाव भय मुक्त वातावरण में हो सके।

नक्सली हमले का 2024 कनेक्शन?

डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) को माओवादी अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं

जितेंद्र भारद्वाज

छत्तीसगढ़ में दत्तेवाड़ा के अरनपुर गांव के निकट 26 अप्रैल को हुए नक्सली हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के दस जवान शहीद हो गए थे। यह हमला इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के जरिए किया गया था। सड़क किनारे दबाई गई आईईडी के ऊपर से जैसे ही गाड़ी गुजरी, वह ब्लास्ट की चपेट में आ गई। इस हमले के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), दरभा डिविजन कमिटी के सचिव साइनाथ की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, माओवादी पार्टी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्मूलन करने के मकसद से इन इलाकों में ऑपरेशन करा रहे हैं। बस्तर में अलग-अलग तरह के सैनिक, अर्धसैनिक बल, एनएसजी, डीआरजी और कोबरा जैसे कमांडो बलों को उतारकर कर इसे एक छावनी बना दिया गया है। माओवादियों ने अपने पत्र में डीआरजी जैसी बहादुर फोर्स को गुंडा बताया है। डीआरजी में भर्ती के लिए योग्यताएं व मापदंड बदल दिए गए हैं। केवल शिकार करने में माहिर लोगों को डीआरजी में भर्ती किया जा रहा है।

बस्तर क्षेत्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से हमला

माओवादियों ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि बस्तर क्षेत्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से हवाई हमला किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले साल भी हवाई हमले की बात सामने आई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने ऐसा कुछ होने से इनकार किया था। अरनपुर में हुए हमले को लेकर नक्सलियों का कहना है कि डीआरजी के लोग गांवों



में सर्चिंग के नाम पर हमला कर लौट रहे थे। पीएलजीए ने लौटते वक्त इस हमले को अंजाम दिया है। नक्सलियों को %डीआरजी% से कितनी शत्रुता है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी विज्ञप्ति में लिखा है, बस्तर इलाके में पुलिस नौकरियों में भर्ती के लिए योग्यताओं व मापदंडों को बदल दिया गया है। अनपढ़ और शारीरिक तौर से अनफिट लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वे लोग शिकार करने में माहिर हैं। हथार हैं, इसलिए उन्हें भर्ती में पहली प्राथमिकता मिल रही है।

आगे भी डीआरजी पर हमले जारी रखेंगे

नक्सलियों ने अपने संदेश में अदाणी और उनकी संपत्ति का भी जिक्र किया है। सरकारें, पुलिस विभाग को छोड़कर, बाकी जगहों पर नियुक्तियां बंद कर रही हैं। पुलिस के लिए जारी संदेश में उन्होंने कहा, वे जानते हैं कि मजबूरी में स्थानीय लोगों को पुलिस की नौकरी करनी पड़ रही है। पुलिस को

चेतावनी देते हुए नक्सलियों ने कहा, वे जनता पर होने वाले हमलों से दूर रहें। उन्हें जनता का साथ देना चाहिए। पुलिस, हवाई हमले जैसी कार्रवाई से दूर रहे। अपनी विज्ञप्ति में नक्सलियों ने दो बार हवाई हमलों का जिक्र किया है। उनके संदेश की भाषा बताती है कि वे भविष्य में भी डीआरजी पर हमले जारी रखेंगे। वे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड को माओवादी, अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। साल 2008 में सबसे पहले बस्तर में ही डीआरजी की भर्ती हुई थी। कांकर व नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में डीआरजी को उतारा गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की भर्ती शुरू हुई। सुरक्षा बलों के एक अधिकारी के मुताबिक, डीआरजी को इसलिए ये लोग अपना बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि अधिकांश जवान पूर्व में नक्सलियों के समूह में शामिल रहे हैं। उन्हें नक्सलियों के छिपने के ठिकाने, जंगल से बाहर आने का रास्ता, सप्लाइ चैन और सुरक्षा बलों पर हमला करने की रणनीति, मालूम होती हैं। इन जवानों को सीआरपीएफ के साथ विभिन्न ऑपरेशनों में भेजा गया है। आत्मसमर्पण करने के बाद एक तय अवधि पूरी होने पर ही उन्हें डीआरजी में भर्ती किया जाता है। इसके बाद भी लंबे समय तक उन पर नजर रखी जाती है। जब भरोसा पूरी तरह से पुख्ता हो जाता है, तो ही उन्हें स्वतंत्र तरीके से ऑपरेशन की कमान सौंपते हैं। इस बीच उनसे इंटरलिंगेंस का काम भी कराया जाता है। डीआरजी को कुछ हद तक गुरिखा युद्ध पद्धति की भी ट्रेनिंग देते हैं।

जाको राखे साईया मार सके ना कोय

छत्तीसगढ़ के अरनपुर में नक्सलियों ने डीआरजी पर जो हमला किया है, उसमें जाको राखे साईया मार सके ना कोय कहावत सही साबित होती है। हमले में बाल-बाल बचे ड्राइवर युवराज सिंह बताते हैं, जब डीआरजी के जवान ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त काफिले में करीब दो दर्जन वाहन थे। नक्सलियों ने तभी हमले की प्लानिंग की होगी। उन्हें लगा होगा कि आते समय भी इतने ही वाहन होंगे। हालांकि अधिकांश गाड़ियों तो वहीं पर रह गई थीं। हमारे काफिले में तीन वाहन थे। आईईडी ब्लास्ट में वाहन उड़ने से डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए हैं, वह तुपान गाड़ी नंबर तीन थी। नंबर दो वाली ब्लैक स्कोरपियो, जिसे युवराज सिंह चला रहे थे, उसके नीचे लकड़ी फंस गई थी। वह उसे निकालने के लिए उठरा। उसके बाद जैसे ही काफिला आगे बढ़ा तो ड्राइवर ने तीसरे नंबर वाली गाड़ी को स्क्रॉपियो से आगे निकाल दिया। हालांकि वह ड्राइवर कभी ओवरटेक नहीं करता था। काफिले में जिस भी नंबर पर जो गाड़ी होती है, वह आखिरी प्वाइंट पर पहुंचने तक उसी क्रम में रहती है। अरनपुर में उस ड्राइवर ने ओवरटेक कर दिया। कुछ ही सेकेंड बाद वही गाड़ी आईईडी ब्लास्ट हो गई। तबतौर युवराज सिंह, अगर तीसरे नंबर की गाड़ी ओवरटेक नहीं करती, तो ब्लास्ट की चपेट में उसकी गाड़ी आनी थी। युवराज की गाड़ी में एक एएसआई सहित आठ जवान सवार थे।



रायपुर। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

कर्नाटक में चुनाव आयोग के समक्ष पार्टियों की शिकायत

■ भाजपा के बाद अब कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग, शाह और योगी के प्रचार करने पर उठाए लाने की मांग की

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भाजपा चुनाव आयोग पहुंची थी। अब कांग्रेस भी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने भाजपा के



शीर्ष नेतृत्व विशेष तौर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक और धामक टिप्पणियों के खिलाफ शिकायत की गई। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानों के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल,

मुकुल वासनिक सहित कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष दो तीन विषय उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भाजपा के बड़े नेताओं के बयान हैं। हमने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं ने तीन-चार ऐसे बयान दिए हैं जो उकसाने वाले, सांप्रदायिक, आपसी वैमनस्य और नफरत फैलाते हैं। सिंघवी ने कहा कि भाजपा के नेताओं की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं तथा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने

शुक्रवार को चुनाव आयोग से कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी जहरीली सांप टिप्पणी को लेकर आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से भी उन्हें बाहर करने की बात कही है। केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा का एक दल निर्वाचन आयोग से मुलाकात करने पहुंचा था। मुलाकात के बाद केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि खड़गे की जहरीला सांप संबंधी टिप्पणी वैमनस्य और नफरत फैलाते हैं। सिंघवी ने कहा कि भाजपा के नेताओं की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं तथा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने

वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराया में रियायतों की बहाली वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रेलवे द्वारा कोविड महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली ट्रेन किराए में रियायत की बहाली की मांग की गई थी। अदालत का कहना है कि चूंकि यह शासकीय नीति का मामला है इसलिए अदालत के लिए सरकार को निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ एमके बालाकृष्णन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बंद की गई रियायतों की बहाली की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में परमादेश रिट जारी करना इस अदालत के लिए उचित नहीं होगा।

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच, अदालत ने आबकारी मनी-लॉन्डिंग मामले में सह-अभियुक्त राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेशों को 6 मई तक के लिए टाल दिया। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दावा किया गया है कि जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जांच 'महत्वपूर्ण' चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनागढ़त ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी।

समलैंगिक विवाह को लेकर संत समाज में रोष

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच में समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले विभिन्न पक्ष अपने-अपने माध्यम से इसे लेकर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने से भारतीय विवाह परंपरा और परिवार संस्था संकट में पड़ जाएगी। इस मुद्दे के विरोध में देश के 428 जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन देने का काम शुरू किया गया है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के विधिक विभाग ने अयोध्या की दो दिवसीय बैठक में एक प्रस्ताव पास कर समलैंगिक विवाह का विरोध करने का निर्णय किया था। इसके पूर्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी समलैंगिक विवाह को सही न मानते हुए यह मामला देश की संसद पर छोड़ने की बात कही थी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) दिल्ली प्रांत ने शुक्रवार को समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के मामले पर कड़ा विरोध जताया है।

पालघर में 2 साधुओं की हत्या की जांच करेगी सीबीआई

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पालघर मांब लिंचिंग मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाएगी। यह मामला अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर जिले के गडचिंचल गांव में भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके कार चालक की पीट-पीट कर हत्या करने का है। 16 अप्रैल 2020 को, तीन पुरुष - दो द्रष्टा और उनका कार चालक अपने आध्यात्मिक गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात के सूरत पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिनका निधन हो गया था। तीनों लोग महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर एक पुलिस चौकी से वापस लौटे और गांवों से होकर जाने वाली आंतरिक सड़कों से सूरत पहुंचने की कोशिश की। गडचिंचल गांव में और उनके आसपास बच्चा चोरों के घूमने की अफवाहें घटना से पहले कम से कम दो सप्ताह से व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रही थीं।

22 जनवरी होगी रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा

नई दिल्ली। अयोध्या रामजन्मभूमि में निर्माणाधीन राममंदिर के भूतल का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। रामलाला के प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी शुरू हो गई है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने काशी के विद्वानों से प्राण प्रतिष्ठा की तीन शुभ तिथि मांगी थीं। विद्वानों द्वारा 22 जनवरी की तिथि को शुभ बताया गया है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना है कि जनवरी 2024 तक रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य गर्भगृह में कर दी जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने काशी के दिग्गज विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ से तीन मुहूर्त मांगे थे। 15 जनवरी से 25 जनवरी 2024 के भीतर यह मुहूर्त निकालने को कहा गया था। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने 22 जनवरी 2024 का मुहूर्त निकाला है। इसके अलावा उन्होंने फरवरी में भी एक मुहूर्त निकालकर ट्रस्ट को बताया। ज्योतिषविद् आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने ही जन्मस्थान पर भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के लिए मुहूर्त निकाला था।

फिर 11 जवानों की हत्या, नक्सली तांडव आखिर कब तक?

संजीव ठाकुर

विगत दिनों नक्सलियों द्वारा पुलिस वालों की वृहद रचना तोड़ते हुए नक्सलियों ने एंड्रुश लगाकर 11जवानों की दत्तेवाड़ा जिले में दर्दनाक हत्या कर दी, लगभग और जवान घायल भी हुए हैं, नक्सलियों का दो साल बाद का सबसे बड़ा हमला है। इसके पूर्व 2 वर्ष पहले एक विधायक की हत्या कर दी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि खुफिया तंत्र को असफलता तथा नक्सलियों तक पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी पहुंचने के कारण नक्सलियों ने तांडव मचाया है। केन्द्रीय गृहमंत्री तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोनों ने दुख व्यक्त कर पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ाया और यह भी कहा कि यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलियों ने लगभग दो साल बाद छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपनी उपस्थिति फिर से

दर्शाई है। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर, जसपुर, बस्तर, दत्तेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, नारायणपुर आदि धुर नक्सली क्षेत्र माने जाते हैं और नक्सली अपनी गतिविधि यहां लगातार दर्शाते रहते हैं। लेकिन यह 11 जवानों की हत्या बड़ी ही दर्दनाक हुई और अचानक नक्सलियों द्वारा आक्रमण की रणनीति के कारण अभी तक प्रशासन शासन को समझ नहीं आया है। क्षेत्र की जनता और सरकार दोनों अब हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया विभाग अपने असफलता के कारणों की खोज में लगी हुई इतना बारूद सड़कों में लगाया गया और पुलिस के खुफिया तंत्र को कानों कान खबर नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार के जंगलों में नक्सलवादियों ने अपना केंद्र बना कर रखा है, और गाहे-बगाहे पुलिस से मुठभेड़ में पुलिस वालों की अनावश्यक हत्या करते रहते हैं।



विगत दिनों नक्सली नेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ की पुलिस के केंद्रीय बल के सैनिकों पर इतना बड़ा हमला कर दिया। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सरकार को नक्सली समस्या का स्थाई हल खोजना ही होगा अन्यथा इस तरह की नक्सली मुठभेड़ में जवानों की जिंदगी व्यर्थ ही गवानी पड़ जाएगी। नक्सली समस्या मूलतः

पश्चिम बंगाल की देन है, जहां चारू मजूमदार, कानू सात्याल के नेतृत्व में नक्सलवादी नामक ग्राम में दल का गठन किया गया था। जहां सरकार के विरोध में आदिवासियों के शोषण और सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के विरोध में चारू मजूमदार ने एक अभियान चलाया था। कालांतर में जो नक्सलवादी गतिविधि या वामपंथी गतिविधि के नाम से जानी जाती है। कई वर्षों पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रशासनिक कुशलता दिखाते हुए कठोर कदम उठाकर नक्सलवादी को समूल नष्ट करवा दिया था। इसी तरह पंजाब में खालीस्तान समस्या सिर चढ़कर बोलने लगी थी। जिससे पंजाब की जनता अनावश्यक परेशान थी, और खालीस्तान के समर्थक वहां हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो कर सरकार को सरकार चलाने में दिक्कत देने लगे थे।

ऐसे में पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के,पी,एस गिल ने एक कठोर ऑपरेशन चलाकर खालीस्तान समस्या को नेस्तनाबूद कर दिया था। नक्सली तथा वामपंथी समस्याओं से प्रभावित झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों को नक्सलियों के विरोध में इसी तरह संयुक्त अभियान चलाकर नक्सली समस्या को कठोरता से खत्म करना चाहिए। या फिर शासन प्रशासन को नक्सली समस्या पैदा होने के मूल कारणों में जाकर वहां की आदिवासी जनता को राशन, दवाएं, पानी, शिक्षा और सड़क की समस्या को समझ कर उस क्षेत्र को सामाजिक अभियान चलाकर नक्सली मुक्त करना चाहिए। क्योंकि नक्सली मुक्त कराना ही पुलिस दल से ज्यादा आधुनिक अस्त्र शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल कर पुलिस वालों को लगातार मौत के

घाट उतार कर शासन का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अब तक नक्सलवादियों ने हजारों पुलिसकर्मियों की हत्या की है। यह विद्रोही, माओवादी आदिवासियों को राशन पानी स्वास्थ्य शिक्षा सड़क की सुविधाएं न दिए जाने की आड़ में उनसे सहयोग लेकर पुलिस वालों की निरंतर हत्या कर रहे हैं। जिसे तत्काल एक अभियान बनाकर तो रोकना चाहिए, इन राज्यों में दूरगामी योजना बनाकर सिद्धार्थ शंकर रे जैसे प्रशासक तथा केपीएस गिल के अधिकारियों की आवश्यकता फिर से होगी। इसके अलावा नक्सलियों को खत्म करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति तथा सशक्त दूरगामी रणनीति तैयार कर इन को घेरकर समाप्त किया जाना चाहिए अन्यथा ऐसे ही मुठभेड़ों में निरीह जवानों की हत्या होती रहेगी और हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे।

भाजयुमो ने बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे को लेकर किया कलेक्ट्रेट घेराव

पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने बैरिकेड्स और पानी का छिड़काव करने फायर ब्रिगेड का किया इस्तेमाल

मुंगेली। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मुंगेली ने बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने बैरिकेड और पानी का छिड़काव फायर ब्रिगेड किया अंततः कलेक्टर पहुंचकर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विधायक पुत्रलाल मोहले के नेतृत्व में अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश के आह्वान पर बेरोजगारों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा भत्ता आदि देने में किए जा रहे छल के विरोध में जिला भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर करही कलेक्ट्रेट के लिए निकले रास्ते में दाऊपारा चौक में नुकड़ सभा के माध्यम से जनता को भूषण बघेल सरकार की नाकामियों और बेरोजगारों के साथ किए जा रहे छल के विरोध में बताया गया। युवा मोर्चा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के पहले लगाए गए बैरिकेड के पास पहुंचे। इसके पश्चात बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास किया



तब पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को रोकने डंडे आदि से उनके हाथों को चोट पहुंचाया गया। उन्हें बैरिकेड पर चढ़ने से रोका गया, साथ ही फायर ब्रिगेड से तेज धार पानी का बौछार कार्यकर्ताओं के ऊपर किया। इसके बावजूद कार्यकर्ता अंततः कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधायक पुत्रलाल मोहले, जिला भाजपा अध्यक्ष

शैलेश पाठक, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष तरुण खाण्डेकर के नेतृत्व में अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल को मुख्यमंत्री भूषण बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पुत्रलाल मोहले ने क्षेत्र की अन्य समस्याओं जैसे अवैध प्लांटिंग, छोटे प्लांटों की रजिस्ट्री नगर व ग्रामीण सभी क्षेत्र के लिए खोलने अथवा पूर्णरूप

से बंद करने की मांग की। आदि के विषय में बात करते हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं पर उनके हाथों को लात मारने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष शैलेश पाठक ने बेरोजगारी भत्ता को बेरोजगारों के साथ छल बताया। युवामोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण खाण्डेकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे। उन्हें विभिन्न नियम कानून में फंसा कर उनके साथ छल ना करे। अवैध प्लांटिंग व छोटे रजिस्ट्री नगर ग्रामीण सभी क्षेत्र के लिए खोलने अथवा सभी क्षेत्रों के लिए बंद करने की मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश शुक्ला, शैलेश पाठक, लक्ष्मीसेवक काठक, गुरुमीत सलूजा, धनेश

साहू, उमाशंकर साहू, धनीराम, रजनी मानिक सोनवानी, दुर्गा उमाशंकर साहू, राणाप्रताप सिंह, प्रदीप मिश्रा, श्रीकांत पाण्डेय, रवि शर्मा विनय साहू महाजन जायसवाल, शंकर सिंह, प्रद्युम्न तिवारी, नितेश भारद्वाज, मुकेश लोहार, विश्वास दुबे, कोटमल दादवानी, प्रदीप पाण्डेय, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण खांडेकर, जिला महामंत्री अमितेय आर्य, माधव तिवारी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य यश गुप्ता, अनुराग सिंह, उमाशंकर बघेल, हरीश चंद्र यादव, हैप्पी ठुरा, मिथिलेश केशरवानी, अरविंद सिंह राजपूत, रिंकू सिंह ठाकुर, संदीप साहू, अनिल दुबे, करण सिंह, अभिषेक पाठक, सौरभ वाजपेयी, संदीप सोनी, तामेश्वर साहू, हरिभजन सिंह, तरुण साहू, पंकज वर्मा, राजेन्द्र साहू, उत्तम साहू, धनराज सिंह परिहार, राजा तम्बोली, राजेश्वर टंडन, केशव साहू, घनश्याम यादव, आदि मुंगेली जिले के समस्त 9 मंडलों से आए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित रहे।

नक्सलियों ने हर्षा कोडेर में लगे जिओ टावर में की आगजनी

दत्तेवाड़ा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में लगातार नक्सली वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दो दिन पहले बुधवार को ही अरनपुर में आईडी ब्लास्ट कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद नारायणपुर में सड़क काटने की घटना को अंजाम दिया था। अब बीती रात गुरुवार को नक्सलियों ने अबुल्लाड़ क्षेत्र में हर्षा कोडेर गांव में जिओ कंपनी के टावर को आगजनी कर दहशत फैला दी है। मलेवाही थाना से तीन किलोमीटर दूर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने बारसूर पल्ली मार्ग पर हर्षा कोडेर गांव में लगे जिओ टावर में आगजनी की घटना को गुरुवार रात अंजाम दिया है। बता दें कि अबुल्लाड़ के इस क्षेत्र में अभी हाल ही में नेटवर्क की सुविधा शुरू हुई थी। नक्सलियों ने उसी टावर में आगजनी कर दी है। नक्सलियों ने मौके पर बैनर भी लगाए हैं। जिस पर कारपोरेट कारण, सैनिक कारण, पुलिस, सड़क, पुलिस, कैम्प का विरोध, जन संघर्ष को तेज करें, पल्ली बारसूर सड़क पर सवारी गाड़ी चलाना बंद करें, आमदई खादन, बोदघाट रद्द करो, जल जंगल जमीन बचाने आगे आने की बात लिखी हुई है। साथ ही आमदई एरिया कमेटी द्वारा घटना को अंजाम देने बताया है। इसके अलावा मुखबिर का काम करने वाले जनता के सामने आ कर अपनी गलती मानने की बात कही गई है। वहीं गलती न मानने पर सागर साहू व रामधर जैसे मौत दिए जाने की बात भी लिखी गई है। बारसूर थाना प्रभारी राजेन्द्र पामभोई ने बताया कि आगजनी की घटना हुई है। टावर को आंशिक नुकसान हुआ है।



संग्राहकों को तेंदूपत्ता की तरह फूड ग्रेड महुआ पर मिलेगा बोनस राशि

कोरबा। तेंदूपत्ता संग्राहकों की तरह अब फूड ग्रेड महुआ संग्रहण करने वाले संग्राहक परिवारों को बोनस राशि मिलेगी। फूड ग्रेड महुआ वह है जिसे जमीन पर गिरने से पहले जाल लगाकर संग्रहित किया जाता है। इस बार कोरबा व कटघोरा वन मंडल से 730 क्विंटल महुआ संग्रहित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 115 रुपये तय किया गया है। संग्राहकों यह महुआ 10 रुपये में खरीदी गई है। सुखने से लेकर पैकिंग तक आने वाली खर्च को काटकर शेष राशि संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी।



जिले में अब तक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को संग्रहण के एवज में बोनस राशि दी जाती थी, अब महुआ संग्रहण में भी बोनस मिलने से परिवारों को दोहरा लाभ मिलेगा। जिले में फूड ग्रेड महुआ संग्रहण का यह दूसरा वर्ष है। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरबा वन मंडल के बड़मार, लेमरू, करतला व कटघोरा वन मंडल के ग्राम जटया में फूड ग्रेड महुआ का संग्रहण किया है। प्रत्येक गांव में 20-30 संग्राहक परिवार महुआ संग्रहण से जुड़े हैं। महुआ संग्रहण के लिए 120 संग्राहक परिवारों को जाली प्रदान की गई थी। जिन संग्राहक परिवार के निजी जमीन में 10 से भी अधिक महुआ पेड़ हैं जिनका चयन किया गया था। संग्रहित महुआ को निश्चित ताप व दाब में सुखाया जाता है। साथ ही इस बात का खयाल रखा जाता है कि व काला न होने पाए। महुआ को औषधि, चिरोन्जी के साथ लड्डू व शुष्क लाटा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बीते वर्ष दोनों वन मंडलों से 526 क्विंटल महुआ संग्रहित किया गया था। कटघोरा वन मंडलाधिकारी प्रेमलता यादव ने बताया कि संग्रहित फूड ग्रेड महुआ को लघुवनोंपत्र संग्रहण केंद्र रायपुर भेजा जाता है। जहां से आनलाइन बिक्री की जाती है। बीते वर्ष कोरबा के महुआ की खरीदी ईलैंड के एक संस्था ने की थी। इस वर्ष जिले के दोनों वन मंडलों से मिले 650 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ को कटघोरा वनमंडल कार्यालय के वनोपज संग्रह कक्ष में रखा गया है। जिसे रायपुर भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी खासी मांग है। बीते वर्ष बिक्री की गई महुआ का अभी संग्राहकों को बोनस राशि नहीं दी गई है। इस वर्ष संग्रहित महुआ की बिक्री के पश्चात एक साथ दो वर्ष की बोनस राशि दी जाएगी।

प्राथमिक शालाओं में मनाया गया 'अंगना म शिक्षा 3.0' कार्यक्रम

मुंगेली। कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में 25 अप्रैल को सुष्कर पदवईया के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जिले के सभी प्राथमिक शालाओं में 'अंगना म शिक्षा 3.0' कार्यक्रम के तहत शिक्षा मेला 'पढ़ई तिहार' मनाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस तिहार में लगभग 5987 माताओं ने अपने बच्चों के साथ आकर मेला का आनंद लिया। इस तिहार में विभिन्न गतिविधियों एवं सामान के माध्यम से 03 से 05 वर्ष के बच्चों की माताओं को शिक्षा के महत्व एवं बच्चों की शाला भेजने के पूर्व तैयारी, घरेलू सामग्रियों का उपयोग करके गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के तरीके सिखाए गए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में गाँव में लोगों को हर क्षेत्र में शिक्षित करने तथा सस्वी, फल, खिलौने, बर्तन, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, रस्सी, कार्ड, गिट्टियाँ आदि का प्रयोग कर अंगना मा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने संबंधित जानकारी दी गई। जहां तीनों विकासखंड में अंगना म शिक्षा पढ़ई तिहार, नौ काउंटर के द्वारा बच्चों के शारीरिक विकास, सामाजिक, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भाषायी विकास, गणित पूर्व तैयारी, वर्गीकरण, वर्णमाला, संख्या जान, आकार, रंग के साथ ही संख्याओं के बारे में समझाया गया। इस अवसर पर जिला मिशन समन्वयक ओ. पी. कौशिक, सहायक कार्यक्रम समन्वयक अशोक कश्यप, यू. के. शर्मा और संजय साहू उपस्थित थे।

शिक्षक पदोन्नति काउंसिलिंग के दौरान थम नहीं रहा आरोप-प्रत्यारोप

कोरबा। जिले में 1145 शिक्षकों का प्रधानपाठक पद में पदोन्नति काउंसिलिंग में आरोप, प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा। दीपका प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका सावित्री का कहना है व हार्ट की मरीज है और जिस स्कूल में पदस्थ है व प्रधान पाठक बनने के लिए पात्र है। इसके बावजूद भी उसके स्थान पर पाली विकासखंड के किसी दूसरे शिक्षक को पदस्थ कर दिया गया है। इस तरह की कई शिकायतों के साथ अब शिक्षक कलेक्टर कार्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। प्रायमरी स्कूलों में पदस्थ सहायक शिक्षक से पदोन्नत होकर प्रधानपाठक बनने पर पदस्थापना के लिए जिला स्तरीय काउंसिलिंग गुरुवार को भी जारी रही। अंतिम चरण की में बुलाए गए 300 प्रधानपाठकों की काउंसिलिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई। विद्युत गृह स्कूल क्रमांक एक में चल रही काउंसिलिंग के तीसरे दिन भी वरीयाता क्रम में पदांकन पाते स्कूल चुनने प्रधानपाठकों को बुलाया गया। काउंसिलिंग टीम के समक्ष पहुंचने पर पसंद का स्कूल नहीं मिलने से अधिकांश नाराज प्रधानपाठक नाराज दिखे। वहीं जिनकी पदस्थापना हो गई, वे खुश नजर आए। काउंसिलिंग में कुछ ऐसे प्रधानपाठक भी थे, जो जहां पदस्थ रहते हुए पदोन्नत



हुए हैं और वहां प्रधानपाठक का पद खाली है। इसके बाद भी उन्हें दूसरी जगह पदस्थ कर दिया गया है। ऐसे लोग अपने पसंद के स्कूल में पदस्थापना की मांग करते रहे लेकिन उन्हें नहीं दी गई। प्रधान पाठक जेपी कोसले का कहना है कि पदस्थापना को लेकर नियम का पालन नहीं किया गया। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर से की है। इसका होगा कि असंतुष्ट शिक्षकों ने अब कोर्ट जाने का मन बना लिया है। कोर्ट में फिर से अपील की गई तो प्रक्रिया फिर से निरस्त होने की आशंका बढ़ गई है। शिक्षकों की हडताल व धरना प्रदर्शन से पहले ही शिक्षा का स्तर दयनीय है। पदस्थापना को लेकर यही दशा रही तो आगामी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई बाधित होगी। पदोन्नत प्रधानपाठकों को काउंसिलिंग के माध्यम से जिले के सभी ब्लॉकों के प्रायमरी स्कूलों में रिक्त पदों पर पदांकित करने का प्रावधान है। तीन दिवसीय काउंसिलिंग में पदोन्नत हुए दिव्यांग, गंधीर बीमारी से ग्रस्त महिला व पुरुष के क्रम से पदांकन करना था। शिक्षकों का आरोप है कि नियम से हटकर समाप्त महिलाओं को भी पदोन्नति में वरीयता दी गई है। काउंसिलिंग स्थल में विगत तीन दिनों से शिक्षकों की शिकायत की भरमार रही। शिक्षक संस्कार चौरसिया ने कहा कि सर मैं घर का अकेला सदस्य हूँ। माता-पिता बुजुर्ग हैं, घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं बहुत परेशान हूँ। काउंसिलिंग टीम मेरी परेशानी को समझे। इस पर काउंसिलिंग टीम ने दूसरे स्कूल के विकल्प की बात कही तो उसने कहा कि मुझे किसी और स्कूल में नहीं जाना है, जमनीपाली ही चाहिए। 18 साल तक घर से दूर रहकर काम कर रहा हूँ, अब मुझे मनपसंद स्कूल चाहिए। इस तरह के विवाद से काउंसिलिंग घंटों प्रभावित रहा। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक से अश्विनी कुमार नामक शिक्षक ने काउंसिलिंग टीम से कहा कि सर मुझे अब अपनी पत्नी के साथ रहना है। मुझे शहरी क्षेत्र का एक स्कूल दे दिया जाए। हालांकि काउंसिलिंग टीम उनके दस्तावेजों को देखने के बाद इन्हें भी दूसरा स्कूल विकल्प के रूप में चयन करने कहा।

मुनेश्वर साहू हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा। बेमेतरा के बिरनपुर में हुए हिंसक झड़प में मुनेश्वर साहू के हत्या मामले में नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने आरोपी कल्लू उर्फ राशिद खान को बिरनपुर से ही गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बिरनपुर में 8 अप्रैल को हुई हिंसा मामले में आरोपी कल्लू उर्फ राशिद खान भी शामिल था। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को बेमेतरा के बिरनपुर में दो समुदाय के बीच हिंसा हुई थी। जिसमें एक भुजनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हत्या के बाद गांव में आगजनी की घटना भी हुई। जिसमें सिलेंडर विस्फोट भी हुआ। गांव में हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और लगभग एक हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया था।



नया अध्यक्ष ने किया जनता की समस्या का निराकरण

दल्लैराजहरा। वार्ड क्रमांक 19 सुभाष चौक में शनिवार दिनांक 22 तारीख को चले हुए आंधी तूफान बारिश से महुआ पेड़ क्षतिग्रस्त हो चुका था और राहगीरों के ऊपर जान का खतरा बन रहा था व गिरने की कगार पर था जिसमें जनता की विशेष मांग पर नगर पालिका अध्यक्ष शिवू नायर अपनी टीम के साथ वार्ड क्रमांक 19 सुभाष चौक पहुंचकर क्षतिग्रस्त पेड़ को कटवाया व तत्काल बिना मन रोड को प्रभावित किए कटे हुए पेड़ को वहां से हटाया, जिससे वार्ड क्रमांक 19 की जनता आने जाने वाले लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष शिवू नायर व उनकी टीम वार्ड क्रमांक 8 के पाषंड स्वप्निल तिवारी स्पोर्ट्स सेल के जिला अध्यक्ष विलियम भंवरा वार्ड क्रमांक 23 के पाषंड जससू नायक युवा नेता जसविंदर सिंह गिल नगर पालिका के समस्त कर्मचारीयो का आभार व्यक्त किया।



सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में करतला में 100% कार्य पूरा

कोरबा। बरपाली सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य तीव्र गति से जारी है कोरबा जिले के विकास खंड करतला ने समाचार लिखे जाने तक सौ प्रतिशत से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है अभी भी तीन दिन बचे हुए हैं तीस अप्रैल तक सर्वेक्षण का कार्य करना है अभी और प्रतिशत बढ़ने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। कोरबा जिले के अंतर्गत विकास खंड करतला सबसे पहले सौ प्रतिशत प्राप्त करने वाला विकास खंड बना है। जनपद पंचायत करतला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम प्रस नगेश ने बरपाली पहुंच कर सर्वेक्षण टीम के प्रगणको का कार्य देखा एवं भरे हुए फर्मों का निरीक्षण भी किया तथा सभी प्रगणको को पंचायत भवन में बैठकर लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए एवं अभी भी कुछ बचे हुए सर्वे घरों को चिन्हंकित कर सर्वेक्षण में लाने को कहा। इस निरीक्षण के अवसर पर करारोपण अधिकारी दादू सिंह कंवर, प्रगणको में संतोष राठी, एस के तांडिया, आर एन कंवर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि उपस्थित थे।

45 मवेशियों से भरे कटेनर को ग्रामीणों ने पकड़ा

जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस ने 45 मवेशियों से भरे कटेनर के साथ दो तस्करी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि, आरोपी मवेशियों से भरे कटेनर को ग्राम धरदेई से हैदराबाद के बुचडुखाने लेकर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार, पकड़े गए दोनों आरोपी मोहन बीडी (25 वर्ष) और रविराज (26 वर्ष) ग्राम बिदरे केमबालु हासन चन्नारायपटना कर्नाटक के रहने वाले हैं। दोनों धरदेई गांव से आवारा पशुओं को ले जाने के लिए आए थे। वे 45 आवारा पशुओं को कटेनर में डालकर, उन्हें हैदराबाद के बुचडुखाने लेकर जा रहे थे। इस दौरान गांववालों की नजर मवेशियों से भरे कटेनर पर पड़ गई। गांववालों ने उनका रास्ता रोका और कटेनर चेक किया। जब मवेशियों के बारे में ड्राइवर मोहन बीडी और रविराज से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मवेशियों को बुचडुखाने ले जाने की बात कही। इसपर ग्रामीणों ने उन दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी और दोनों आरोपियों को उनके हवाले कर दिया।

हाईस्कूल तुमड़ीबहार का परीक्षा परिणाम घोषित

नगरी। आदिवासी विकास खंड नगरी के दूरस्थ वनांचल स्थित शासकीय हाई स्कूल तुमड़ीबहार का सत्र 2022-23 का स्थानीय परीक्षा परिणाम 27 अप्रैल 2023 को घोषित किया गया। संस्था के प्रभारी प्राचार्य सतीश प्रकाश सिंह ने कक्षा नवमी का परीक्षा परिणाम घोषित किया। सत्र 2022-23 में कक्षा नवमी का परीक्षा परिणाम 68 फीसदी रहा। कक्षा में प्रथम कु. ललिता यादव पिता जीवन लाल, द्वितीय कु. तामेश्वरी भंडारी पिता कानन प्रसाद तथा कु. नर्मदा ध्रुव पिता मनोज कुमार ध्रुव तृतीय स्थान पर रहे। संस्था के प्रभारी प्राचार्य सतीश प्रकाश सिंह ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंकसूची प्रदान कर सम्मानित किए। शासकीय हाई स्कूल तुमड़ीबहार का परिणाम घोषित होने पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत डेनही के सरपंच श्रीधन सोम, शाला विकास समिति के अध्यक्ष भानुप्रताप नेतार, शाला विकास समिति के सदस्य विदेश कुमार यादव, संस्था के व्याख्यातागण- राजेन्द्र चिंडा, नंदिनी सोम आदि ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर शुभकामनाएं प्रेषित किए।

बेमेतरा में ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों को काफी नुकसान

■ किसान नेता ने सर्वे कर मुआवजा देने की रखी मांग
■ ओलावृष्टि और तेज बारिश से सजी व प्ला उत्पादक किसानों की फसल खराब
बेमेतरा। ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों को काफी नुकसान हुआ है, बावजूद किसानों को राहत देने के नाम पर सरकार की ओर से अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। इस संबंध में किसान नेता योगेश तिवारी ने ओलावृष्टि से फसल क्षति के सर्वे के साथ-साथ मुआवजा की मांग की है। बेमेतरा जिले में सोमवार को हुई ओलावृष्टि और मंगलवार को हुई तेज बारिश से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। इससे पहले रबी फसल में मुख्य रूप से गेहूँ और चना किसान ने क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और लगभग एक हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया था।

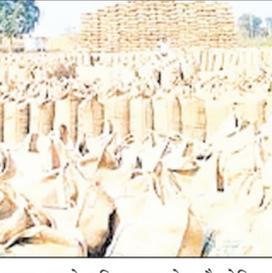


में हुई ओलावृष्टि से सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। काफी बड़े तादाद में फसल बर्बाद भी हुई है। आलम यह है कि किसानों को फसल का लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो गया है।
राज्य सरकार की सर्वे की घोषणा पर नहीं हुआ अमल
किसान नेता योगेश तिवारी के अनुसार राज्य शासन ने सर्वे की घोषणा की थी, जिस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। राज्य शासन पर आरोप

लगाते हुए कहा है कि जब बारिश के हालात बने तो राज्य सरकार ने सर्वे के आदेश दिए, जो सर्वे अब तक नहीं हो पाया है। राजस्व की टीम किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। ना ही किसी तरह की कोई जानकारी दी गई है। ऐसी स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति मिलने पर सवाल खड़े हो गए हैं।
किसान नेता ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
वर्तमान में ओला वृष्टि से किसानों के सब्जी और फल की फसल भी खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में किसानों को दोहरी मार से उबरने का कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा है। लगातार मौसम के बिनाई हालात के कहर से किसान जूझ रहे हैं। किसानों को अब तक कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है। प्रभावित किसानों के संबंध में राज्य शासन कोई उचित समाधान कर मुआवजा की व्यवस्था नहीं किए जाने की स्थिति में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

किसानों के धान खरीदी में शर्त रखना गलत: छान बालोद

बालोद। जिला गन्ना उत्पादक किसान संघ जिला बालोद के संरक्षक छान देशमुख ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आगामी खरीफ सीजन का धान 2800 रु. क्विंटल एवं 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा की है लेकिन इसमें शर्त यह भी रख दिया गया है कि 20 क्विंटल धान समर्थन मूल्य में खरीदेगा तथा 1000 हजार रुपये प्रति एकड़ ही पैसा 4 किस्तों में देंगे इन शर्तों से किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। जैसे की इस वर्ष समर्थन मूल्य 2040 रुपये है तथा अंतर की राशि 2800 रुपये के हिसाब से 760 रुपये आ रहा है। 2040 समर्थन मूल्य तथा अंतर की राशि मिलाकर 2800 रुपये प्रति क्विंटल हो रहा है इस प्रकार 20 क्विंटल की राशि 56000



हजार रुपये प्रति एकड़ होता है लेकिन सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के बाद 9000 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जायेगा तो राशि 49800 रुपये होता है जिसमें किसानों को 6 हजार रुपये का प्रति एकड़ बुकसान हो रहा है यह किसानों के साथ छलावा एवं धोखा है धान खरीदी 2800 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है जबकि गन्ना खरीदी की

कोई घोषणा नहीं की गई है। गन्ना उत्पादक किसान संघ के संरक्षक होने के कारण हम सरकार से मांग करते हैं कि गन्ना खरीद 2023-24 में समर्थन मूल्य के अलावा 200 रुपये प्रति की दर से गन्ना खरीदा जायें तथा धान को भी समर्थन मूल्य के अलावा 750 रुपये प्रति क्विंटल 20 क्विंटल के हिसाब से दिया जाये तभी किसानों के साथ न्याय होगा क्योंकि हम किसान गन्ना के साथ धान की भी खेती करते हैं। उक्त मांग संघ के जिला अध्यक्ष डा. तेजराज साहू उपाध्यक्ष कृष्णा साहू, मनोहर निरन्हा उमेश साहू, दुष्यंत साहू सावंतराम साहू, रोहित देशमुख, ताम्रध्वज ठाकुर, दुलाराम साहू, त्रिलोकी साहू, मिथलेश साहू एवं गन्ना किसानों ने किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण से 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स की शुरुआत की। इन ट्रांसमीटर्स को 18 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी की एफएम सेवा का विस्तार अखिल भारतीय एफएम बन्दे की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह शुरूआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कुछ दिनों बाद मैं रेडियो पर मन की बात की 100वीं कड़ी को संबोधित करूंगा। मोदी ने कहा कि मन की बात का बेहतरीन अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था।



सत्यपाल मलिक के घर पहुंचे सीबीआई अधिकारी

नई दिल्ली। सीबीआई का दल जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले की जांच के तहत पूछताछ करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचा है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि हाल ही में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को केंद्र-शासित प्रदेश में हुए कथित बीमा घोटाले के सिलसिले में कुछ सवालों का जवाब देने को कहा था। इसी सिलसिले में सीबीआई उनके आवास पहुंची है। सात महीने में यह दूसरी बार है, जब मलिक से सीबीआई पूछताछ कर रही है। बिहार, जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारियां समाप्त होने के बाद पिछले साल अक्टूबर में मलिक से पूछताछ की गई थी। सीबीआई द्वारा समन जारी किए जाने के बाद मलिक ने कहा था कि 'वे कुछ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति चाहते हैं।' पूर्व राज्यपाल ने सीबीआई को पूछताछ के लिए 27 से 29 अप्रैल के बीच का समय दिया था।



जयराम रमेश के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। आरोप है कि जयराम रमेश ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। भाजपा सांसद के नोटिस पर सभापति ने इसे राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज दिया है। जांच में अगर जयराम रमेश के खिलाफ लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि जयराम रमेश ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और साथ ही उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। आरोप है कि जयराम रमेश ने बीते बजट सत्र के दौरान कहा था कि सभापति को सत्ताधारी पार्टी का चीयरलीडर नहीं होना चाहिए और विश्व की बात भी सुननी चाहिए। राज्यसभा सचिवालय ने भी कांग्रेस नेता के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस की पुष्टि की है।



स्थानीय लोगों को महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा नहीं : राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि बारसू में स्थानीय लोगों को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर भरोसा नहीं है। मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर रबागिरी में राजापुर तहसील के बारसू के निवासी कई हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल परिसर की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। राकोंपा के अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार को परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों से बातचीत करने की सलाह दी थी। राउत ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि बारसू में जमीन खरीदने वाले नेताओं और 'बाहरी लोगों' के हितों की रक्षा के लिए रिफाइनरी परियोजना को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसे लोगों की सूची सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा, 'मैंने सुना है कि शरद हुए इस साल पुराने सारे रिपोर्ट टूट जाने की उम्मीद है। इस बीच, वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गयी हैं। माना जा रहा है कि इस बार सर्वाधिक संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं क्योंकि कश्मीर के हालात अब पूरी तरह सामान्य हैं। जम्मू-कश्मीर पर्यटन को इस सबसे जहां खूब लाभ हो रहा है वहीं इस केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी काफी सुदृढ़ हुई है।'



पूर्व जदयू नेता अजय आलोक भाजपा में हुए शामिल

नई दिल्ली। पूर्व जदयू (छठ) नेता अजय आलोक भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूँ, जिसके मुखिया मोदी जी हैं। अगर मेरा एक प्रतिशत योगदान भी मोदी विजन में हो सका तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि नीतीश कुमार को बहुत लोग पलटीमार करते हैं, जो बिल्कुल सही है। उन्होंने ही 87 साल बाद जेल मैनुअल में संशोधन किया था और यह क्लॉज डाला था कि अगर सरकारी सेवक की हत्या होगी तो उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। अब आनंद मोहन और बाकी कैदियों को उन्हें रिहा करना इस लिए उन्होंने संशोधन किया।



खड़गे के सांप वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री बोले

कांग्रेस की मति मारी गई है : अमित शाह

बेंगलुरु। कर्नाटक चुनाव लेकर सियासी संग्राम तेज हो गई है। वार-पलटवार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के धारवाड़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया और खुद पर कराए गए एफआईआर पर कहा कि मैं नहीं डरता। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इतना सम्मान करती है, उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल सांप कहते हैं, सोनिया गांधी उन्हें मौत का सोदवार कहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस वालों की मति मारी गई है, वे मोदी जी को जितनी गाली देंगे कमल उतने ही अच्छे से खिलेगा।



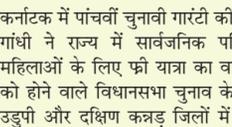
जहरीले नहीं हैं तो छूकर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छूएंगे तो मर जाएंगे।' वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर बृहस्पतिवार को उनके खिलाफ शिकायत दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई तो राज्य 'दंगों की चपेट में रहेगा।' कांग्रेस की शिकायत पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। हमने पीएफआई पर बैंन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं नहीं डरता हूँ।

भाजपा नेता ने यह भी कहा कि आपको कोई आपत्ति है तो आकर बताइए कि क्यों पीएफआई को चालू रखना चाहिए... वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने पीएफआई को सिर पर चढ़ाया था। विपक्षी दल पर हमला जारी रखते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस 70 साल से धारा 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में सहला रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जेडीएस, सपा, बसपा, ममता कहते थे कि इसे मत हटाइए कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। धारा 370 हट गई खून की नदियां तो छोटिए किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी बीजेपी पार्टी है। यह चुनाव यह तय करने के लिए है कि कर्नाटक की जनता इंसान सरकार (बीजेपी) चाहती है या रिवर्स-गियर सरकार (कांग्रेस)।

कांग्रेस सरकार बनी तो महिलाओं का बस में होगा मुफ्त सफर: राहुल

कर्नाटक में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में उथल-पुथल जारी है। सभी पार्टियों मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं बीते गुरुवार को राहुल गांधी ने

कर्नाटक में पांचवीं चुनावी गारंटी की घोषणा की है। राहुल गांधी ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का वादा किया है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस द्वारा चुनावी गारंटी पूरी नहीं किए जाने के संबंध में पीएम मोदी के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चार मौजूदा (चुनावी) गारंटी में हम एक और गारंटी जोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आते ही 5वीं गारंटी भी लागू की जाएगी। जिसके तहत राज्य की महिलाएं सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने 40% कमीशन के जरिए कर्नाटक की महिलाओं के पैसे लूटे। जबकि कांग्रेस का काम राज्य की महिलाओं को कर्नाटक के पैसे का लाभ देना है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद जब भी आप किसी महिला से मिलेंगे, तो उन्हें बसों में यात्रा के दौरान एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से चुनाव गारंटी में गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपए, अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य हर माह 10 किलो चावल की पेशकश की गई है।



कश्मीर में पर्यटकों की भीड़

पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग गदगद, कलाकार भी पहुँचे शूटिंग के

जम्मू-कश्मीर वापस से पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र तो बन ही चुका है साथ ही यहां फिल्मों और वेब सीरिज की भी जमकर शूटिंग हो रही है। इस समय हिंदी फिल्मों के तमाम छोटे बड़े अभिनेता कश्मीर में शूटिंग कर रहे हैं तो दूसरी ओर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए इस साल पुराने सारे रिपोर्ट टूट जाने की उम्मीद है। इस बीच, वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गयी हैं। माना जा रहा है कि इस बार सर्वाधिक संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं क्योंकि कश्मीर के हालात अब पूरी तरह सामान्य हैं। जम्मू-कश्मीर पर्यटन को इस सबसे जहां खूब लाभ हो रहा है वहीं इस केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी काफी सुदृढ़ हुई है।



सभी रिर्कोर्ड्स इस साल टूटेंगे

जहां तक पर्यटकों की बात है तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि वह इस साल जम्मू-कश्मीर में दो करोड़ से ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद कर रहे हैं और यह पिछले साल के रिर्कोर्ड को तोड़ देगा। मनोज सिन्हा ने पत्रकारों से कहा, 9% पिछले साल और इस साल 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है। हम उस रिर्कोर्ड को भी तोड़ेंगे 1% उन्होंने कहा कि हमारी समस्या यह है कि हम अपने ही रिर्कोर्ड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। पिछले साल 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे और मुझे उम्मीद है कि इस साल दो करोड़ से ज्यादा सैलानी आएंगे। हम नए रिर्कोर्ड बनाएंगे और उन्हें तोड़ेंगे।

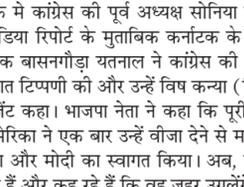
खूब हो रही फिल्मों की शूटिंग

दूसरी ओर, फिल्मों की शूटिंग की बात करें तो हम आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने मंगलवार को कश्मीर घाटी में अपनी आगामी फिल्म 'डेंडकी' की शूटिंग शुरू की। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सोनमर्ग के एक मनोरम पर्यटन स्थल में एक गाने के दृश्यों के फिल्मांकन के साथ

शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग करीब तीन दिन तक चली। फिल्म निर्माण से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'शाहरुख खान सोमवार को कश्मीर के सोनमर्ग पहुंचे थे। सोनमर्ग के थजवास इलाके में सुबह एक गाने के दृश्यों की शूटिंग शुरू हुई। इस गाने को मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया।' इसके अलावा इस समय फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन भी कश्मीर में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 2023 जहां तक अमरनाथ यात्रा की बात है तो आपको बता दें कि जुलाई में शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा उपायों और सैनिकों की तैनाती पर चर्चा के लिए विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की बैठक हुई। हम आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा के लिए दो महीने तक चलने वाली तीर्थ यात्रा एक जुलाई से शुरू होने वाली है और यह 31 अगस्त तक चलेगी। यात्रा दो मार्गों से की जा सकती है- पहली दक्षिण कश्मीर के अंततनाग में पहलगाम के जरिए, जो कि 48 किलोमीटर लंबा मार्ग है और दूसरी मध्य कश्मीर के गान्दरबल जिले से, जो कि 14 किलोमीटर छोटा है लेकिन खड़ी पहाड़ियों वाला मार्ग है।

भाजपा विधायक ने सोनिया गांधी को कहा विषकन्या

बेंगलुरु। अब एक भाजपा विधायक ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर आपत्तजनक टिप्पणी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के कोपल में एक भाषण के दौरान, भाजपा विधायक बासनगौड़ा यतलाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में एक व्यक्तिगत टिप्पणी की और उन्हें विष कन्या (विषाक्त लड़की) और चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहा। भाजपा नेता ने कहा कि पूरी दुनिया ने पीएम मोदी को स्वीकार किया है। अमेरिका ने एक बार उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। बाद में उन्होंने रेड कार्पेट विजया और मोदी का स्वागत किया। अब, वे (कांग्रेस) उनकी तुलना कांग्रेस सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह जहर उगलेंगी। क्या सोनिया गांधी एक जहरीली महिला (विषा कन्या) हैं? उसने चीन और पाकिस्तान के साथ उनके एजेंट के रूप में काम किया। अब इस पर कांग्रेस का पलटवार आया है। उन्नीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक ने सोनिया गांधी को विष कन्या कहा है। कल खड़गे जी के बयान का उन्होंने (भाजपा) पूरे देश में विरोध किया।



संसेक्स 61,100 के ऊपर बंद निफ्टी 18,000 के पार

नई दिल्ली। मिले-जुले वैश्विक रूझानों के बीच लगातार पांचवें दिन घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी निवेश के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं आईटीसी के शेयरों में जोरदार लिवाली से बाजार में तेजी आई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार हर निशान पर बंद हुआ। आज के कारोबार में संसेक्स 463.06 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में 150 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,065.00 पर बंद हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़कर सभी सेक्टरों में इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। आईटी, पीएसयू बैंक और हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा देखा गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक संसेक्स 463.06 अंक यानी 0.76 फीसदी मजबूत होकर 61,112.44 अंक पर बंद हुआ।



पैसा जुटाने के मामले में दुनिया में आगे रहें भारतीय कंपनियां

नई दिल्ली। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पैसा जुटाने के लिए बाजार पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है। कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत में केवल चार कंपनियां ही अपना प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लायी है। हालांकि, इसके बावजूद भारत अन्य देशों के मुकाबले सबसे आगे है। 'इवाइ' ने अपनी आईपीओ ट्रेंड्स रिपोर्ट में कहा कि 2023 की पहली तिमाही में बड़ी कंपनियों के आईपीओ ने कुल 10.7 करोड़ डॉलर के फंड जुटाए। वहीं, पिछले साल की इसी अवधि में तीन कंपनियों ने अपने आईपीओ के जरिये 99.5 करोड़ डॉलर जुटाए थे। इसमें पिछले साल की तिमाही की तुलना में 89 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है।



वोडाफोन आइडिया से भुगतान का बड़ा हिस्सा मिला: इंडस टावर्स

नई दिल्ली। इंडस टावर्स ने कहा कि उसे मार्च तिमाही के लिए वोडाफोन आइडिया से किस्त आधारित भुगतान का बड़ा हिस्सा मिला है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने नतीजे के बाद निवेशकों से बातचीत में यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि उसे वोडा-आइडिया से नई भुगतान योजना का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और कंपनी पिछले बकाए पर नजर बनाए रखेगी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि स्थिति डायनेमिक बनी हुई है। एक दिन पहले टावर कंपनी ने चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ में 23 फीसदी की गिरावट दर्ज की थी, जिसकी वजह राजस्व में गिरावट और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान रही। चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 1,399 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,829 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर राजस्व 5 फीसदी घटकर 6,753 करोड़ रुपये रह गया क्योंकि टावर कंपनी वोडाफोन आइडिया से बकाया वसूलने में चुनौती का सामना करती रही।

स्मार्टफोन के आयात में रिर्कोर्ड गिरावट

नई दिल्ली। भारत का स्मार्टफोन आयात कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत घटकर करीब 3.1 करोड़ इकाई रह गया। काउंटर्पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। यह लगातार तीसरी तिमाही की गिरावट होने के साथ-साथ देश के स्मार्टफोन बाजार में देखी गई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुस्त मांग, वर्ष 2022 के अधिक स्टॉक, रीफर्बिश फोन के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती वरीयता और बाजार के निराशावादी चैनल दृष्टिकोण का इस गिरावट में योगदान रहा। वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक प्राचीर सिंह के मुताबिक हर बीतती तिमाही के साथ 'प्रोमिसमइजेशन' का चलन मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये से कम कीमत वाले वर्ग में पहली तिमाही के दौरान गिरावट जारी रही, इसके आयात में नौ प्रतिशत की गिरावट आई।

श्रीलंका ने आयरलैंड को हराकर टेस्ट सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा

नई दिल्ली। श्रीलंका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के 5वें दिन शुक्रवार को आयरलैंड को पारी और 10 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। पहला टेस्ट भी श्रीलंका ने जीता था। आयरलैंड ने पहली पारी में 492 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन श्रीलंका ने 3 विकेट पर 703 रन बनाकर पारी घोषित किया। श्रीलंका की टीम ने अपनी 100वीं टेस्ट जीत दर्ज की और दो मैच की सीरीज में क्लोन स्वीप किया। श्रीलंका ने पहली पारी में 212 रनों की बढ़त ली। आयरलैंड की दूसरी पारी 202 पर पर सिमट गई। प्रभात जयसूर्या को प्लेयर ऑफ द मैच और कुसाल मेंडिस को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।



ए के भट्टाचार्य

केंद्र सरकार की पिछले माह घोषित नई विदेश व्यापार नीति पर विशेषज्ञों और निर्यात समुदाय ने अलग-अलग टिप्पणियां की हैं। बहरहाल, इस नई नीति का एक अहम पहलू जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया वह है सरकार की यह मान्यता कि नई नीति से निर्यातकों को आने वाले वर्षों में लाभ होगा। नई नीति ने 2030 तक वस्तु एवं सेवा निर्यात को दो लाख करोड़ डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार का वस्तु एवं सेवा निर्यात का लक्ष्य 770 अरब डॉलर है। वर्ष 2029-30 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले सात वर्षों में 14.61 फीसदी की सालाना समेकित वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल करनी होगी। दूसरे शब्दों में देश के सकल घरेलू उत्पाद

(जीडीपी) में वस्तु एवं सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 के 23 फीसदी से बढ़कर 2029-30 में 28 फीसदी होने की उम्मीद है। यह सरकार के इन अनुमानों पर आधारित है कि तब तक देश की अर्थव्यवस्था 7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। बीते एक दशक में वस्तु एवं सेवा निर्यात का सीएजीआर 6 फीसदी से थोड़ा कम रहा। यह सही है कि कोविड ने निर्यात को कम से कम दो सालों तक बुरी तरह प्रभावित किया लेकिन यह भी तथ्य है कि कोविड के बाद के दो सालों में निर्यात में तेज सुधार नजर आया। इस सुधार के बावजूद बीते दशक का सीएजीआर 5.61 फीसदी था। अगर निर्यात को वस्तु एवं सेवा निर्यात में अलग-अलग करके देखा जाए तो हम पाएंगे कि काम और कठिन हो जाता है। वस्तु निर्यात में पिछले 10 वर्षों में 4 फीसदी

दशक में सेवा निर्यात का सीएजीआर करीब 9 फीसदी रहा है। वस्तु निर्यात का आंकड़ा 2021-22 में काफी सुधारा और उसमें 44 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली। परंतु उससे अगले वर्ष यह वृद्धि कम होकर केवल 6 फीसदी रह गई। इससे भी बुरी बात यह है कि करीब एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में (इंजीनियरिंग वस्तु, रब एवं आभूषण, कपास और कालीन, प्लास्टिक लौह अयस्क और कानू आदि) 2022-23 में गिरावट आई। ऐसे में सरकार अगले सात वर्षों के लिए दो अंकों का लक्ष्य क्यों तय करेगी? जब तक वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं की मांग में आमूलचूल बदलाव नहीं आता है तब तक दो लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य दूर की कौड़ी बना रहेगा। तब शायद 2030 में कोई भी सरकार को 2023 में तय किए गए लक्ष्यों के लिए जवाबदेह नहीं मानेगा। सरकार के लिए एक

तरीका यह है कि वह निर्यात लक्ष्य के बारे में ज्यादा न सोचे। अगर कोई लक्ष्य तय करना ही हो तो वह पांच या सात वर्ष की अवधि के लिए नहीं होना चाहिए। सरकार को सालाना लक्ष्य तय करना चाहिए जिसकी निगरानी की जा सके और लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया जा सके। लक्ष्य तय करने से भी अधिक जरूरी यह है कि घरेलू नीतियों के निर्माण पर ध्यान दिया जाए ताकि निर्यात को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। विनियम दर नीतियों को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे निर्यातकों को मदद मिले। आयात शुल्क को भी नीचे लाया जाना चाहिए ताकि निर्यातकों की लागत कम हो सके। आखिर में जैसा कि सन 1990 के सुधार वाले शुरुआती वर्षों में वाणिज्य मंत्री ने सोचा था, अगर विदेश व्यापार नीति महज तीन से पांच पृष्ठों की हो तो ऐसे में निर्यात को अधिक बढ़ावा दिया जा सकेगा।

निर्यात के वास्तविक लक्ष्य और विदेश व्यापार नीति

ए के भट्टाचार्य

केंद्र सरकार की पिछले माह घोषित नई विदेश व्यापार नीति पर विशेषज्ञों और निर्यात समुदाय ने अलग-अलग टिप्पणियां की हैं। बहरहाल, इस नई नीति का एक अहम पहलू जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया वह है सरकार की यह मान्यता कि नई नीति से निर्यातकों को आने वाले वर्षों में लाभ होगा। नई नीति ने 2030 तक वस्तु एवं सेवा निर्यात को दो लाख करोड़ डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार का वस्तु एवं सेवा निर्यात का लक्ष्य 770 अरब डॉलर है। वर्ष 2029-30 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले सात वर्षों में 14.61 फीसदी की सालाना समेकित वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल करनी होगी। दूसरे शब्दों में देश के सकल घरेलू उत्पाद

(जीडीपी) में वस्तु एवं सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 के 23 फीसदी से बढ़कर 2029-30 में 28 फीसदी होने की उम्मीद है। यह सरकार के इन अनुमानों पर आधारित है कि तब तक देश की अर्थव्यवस्था 7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। बीते एक दशक में वस्तु एवं सेवा निर्यात का सीएजीआर 6 फीसदी से थोड़ा कम रहा। यह सही है कि कोविड ने निर्यात को कम से कम दो सालों तक बुरी तरह प्रभावित किया लेकिन यह भी तथ्य है कि कोविड के बाद के दो सालों में निर्यात में तेज सुधार नजर आया। इस सुधार के बावजूद बीते दशक का सीएजीआर 5.61 फीसदी था। अगर निर्यात को वस्तु एवं सेवा निर्यात में अलग-अलग करके देखा जाए तो हम पाएंगे कि काम और कठिन हो जाता है। वस्तु निर्यात में पिछले 10 वर्षों में 4 फीसदी

दशक में सेवा निर्यात का सीएजीआर करीब 9 फीसदी रहा है। वस्तु निर्यात का आंकड़ा 2021-22 में काफी सुधारा और उसमें 44 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली। परंतु उससे अगले वर्ष यह वृद्धि कम होकर केवल 6 फीसदी रह गई। इससे भी बुरी बात यह है कि करीब एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में (इंजीनियरिंग वस्तु, रब एवं आभूषण, कपास और कालीन, प्लास्टिक लौह अयस्क और कानू आदि) 2022-23 में गिरावट आई। ऐसे में सरकार अगले सात वर्षों के लिए दो अंकों का लक्ष्य क्यों तय करेगी? जब तक वैश्विक स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं की मांग में आमूलचूल बदलाव नहीं आता है तब तक दो लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य दूर की कौड़ी बना रहेगा। तब शायद 2030 में कोई भी सरकार को 2023 में तय किए गए लक्ष्यों के लिए जवाबदेह नहीं मानेगा। सरकार के लिए एक

तरीका यह है कि वह निर्यात लक्ष्य के बारे में ज्यादा न सोचे। अगर कोई लक्ष्य तय करना ही हो तो वह पांच या सात वर्ष की अवधि के लिए नहीं होना चाहिए। सरकार को सालाना लक्ष्य तय करना चाहिए जिसकी निगरानी की जा सके और लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया जा सके। लक्ष्य तय करने से भी अधिक जरूरी यह है कि घरेलू नीतियों के निर्माण पर ध्यान दिया जाए ताकि निर्यात को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। विनियम दर नीतियों को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे निर्यातकों को मदद मिले। आयात शुल्क को भी नीचे लाया जाना चाहिए ताकि निर्यातकों की लागत कम हो सके। आखिर में जैसा कि सन 1990 के सुधार वाले शुरुआती वर्षों में वाणिज्य मंत्री ने सोचा था, अगर विदेश व्यापार नीति महज तीन से पांच पृष्ठों की हो तो ऐसे में निर्यात को अधिक बढ़ावा दिया जा सकेगा।

ए के भट्टाचार्य

राहुल गांधी ने छेड़ा जातीय जनगणना का राग

संतोष पाठक

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जिनकी संसद सदस्यता हाल ही में छिन गई है और देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा जिन पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाकर देश भर में अभियान चला रही है, उन राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जातीय जनगणना का राग छेड़ दिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के अंदाज में 2011 में करवाए गए जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस जैसी बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी के नेता आमतौर पर हाल फिलहाल तक इस मुद्दे पर इतने स्पष्ट अंदाज में बोलने से बचते ही नजर आया करते थे लेकिन आजकल कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश में राहुल गांधी ने अब जातीय जनगणना को लेकर भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि कर्नाटक की भरती पर जाकर राहुल गांधी को यह मांग करने की जरूरत क्या थी ? 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार को घटक दलों के दबाव में जिस जातीय जनगणना को कराना पड़ा और जिसका आंकड़ा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार भी जारी नहीं कर पाई थी, आखिर उस आंकड़े को अब राहुल गांधी क्यों जारी करवाना चाहते हैं ? आखिर राहुल गांधी को क्यों इस मसले पर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पीछे-पीछे चलने को मजबूर होना पड़ा ? क्या सिर्फ कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी को जातीय जनगणना और ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा करने का यह राग अलापना पड़ा या फिर इसके तार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक जा रहे हैं ? दरअसल, यह बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक में जीत हार का फैसला ओबीसी समाज के वोटर्स ही करते हैं क्योंकि राज्य में इस समुदाय के मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा यानी 54 फीसदी के लगभग है। पिछले चुनाव में इनमें से सबसे ज्यादा लोगों ने भाजपा को वोट दिया था और ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए राहुल गांधी से जातीय जनगणना को लेकर यह बयान दिलवाया होगा। लेकिन वास्तव में इसकी वजह काफी गहरी है। कर्नाटक में ओबीसी समाज भी अलग-अलग जातियों में बंटा हुआ और हर जातीय समूह का अपना-अपना प्रभावशाली नेता हैं जिनमें से कई अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़े हैं। ऐसे में यह साफ जाहिर हो रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर कर्नाटक के बहाने राहुल गांधी लोक सभा चुनाव के समीकरणों को साधना चाहते हैं। दरअसल, भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर यह दावा करती रहती है कि 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी लोगों के लिए इतने ऐतिहासिक काम किए हैं जो इससे पहले की किसी भी केंद्र सरकार ने नहीं किया था। भाजपा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, केंद्र सरकार में पहली बार ओबीसी समाज के 27 सांसदों को मंत्री बनाने और नवोदय, सैनिक एवं सेंट्रल स्कूलों में ओबीसी छात्रों के लिए 27 फीसदी आरक्षण जैसे कई कदमों का हवाला देते हुए देश भर के ओबीसी मतदाताओं को यह संदेश देने का प्रयास करती है कि उनके समाज के हितों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यही वजह है कि ओबीसी समाज का अपमान करने के आरोपों का सामना कर रहे राहुल गांधी ने भाजपा के इसी प्रचार तंत्र के प्रभाव को तोड़ने के लिए कर्नाटक में जातीय जनगणना के मुद्दे को जोर-शोर से उठा दिया।

महाराष्ट्र की राजनीति के महत्वाकांक्षी भतीजे...

अमिताभ श्रीवास्तव

भारतीय समाज में चाचा-भतीजे का रिश्ता निराला है, जिसके अनेक उदाहरण सहज ही मिल जाते हैं। मगर जब बात राजनीति की हो तो कुछ अलग ही हो जाती है। कब चाचा अपने भतीजे को संभालेगा और कब उसे छोड़ कर आगे निकल जाएगा, कहा नहीं जा सकता। भतीजों का भी मिलता-जुलता हाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में भतीजे हमेशा ही अग्रिम पंक्ति में रहे और अनेक अवसरों पर उन्होंने चाचा को पीछे छोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। ताजा उदाहरण राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के रूप में सामने है। महाराष्ट्र की राजनीति में यूं तो अनेक भतीजे और उनके चाचा छिटपुट स्तर पर हलचल करते रहते हैं, किंतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के भतीजे अजित पवार, पूर्व शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, पूर्व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे और पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल पहली पंक्ति में आकर मुकाबला करते हैं। हालांकि चुनाव हारने और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद भुजबल ने सक्रियता कम रखी है, लेकिन बाकी तीन अपनी महत्वाकांक्षा को उड़ान भरते ही रहते हैं। अजित पवार और राज ठाकरे बार-बार मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना दोहराते रहते हैं। कोई स्पष्ट बोलता है तो कोई एक बार राज्य की डोर अपने हाथों में मांगता है। राजनीति में महत्वाकांक्षा को पालना गलत नहीं माना जा सकता है। उसके साथ संगठनात्मक ताकत, चुनावी विजय का ग्राफ जैसी बातें भी मायने रखती हैं। बीते विधानसभा चुनाव के बाद अजित पवार के राजनीतिक जीवन में दो उतार-चढ़ाव आए। एक जब वह सुबह-सुबह उपमुख्यमंत्री बने और दूसरा जब वह उड़व ठाकरे के नेतृत्व में चौथी बार राकांपा



के उपमुख्यमंत्री बन गए। जब वह सुबह उपमुख्यमंत्री बने तब उनके पास समर्थक विधायकों को दिखाने की आभासी कतार थी, जो वास्तविकता में नहीं बदल सकी। दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बने तो चाचा की पार्टी की तरफ से बन गए। इसके पहले भी चाचा की पार्टी से पद पाने की स्थितियां रहीं। उधर, चाचा से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले राज ठाकरे अपने भाषणों से भीड़ तो इकट्ठी करते रहे, लेकिन उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 13 विधायकों से शून्य पर आ गई है। एक महानगर पालिका मिली थी, वह भी हाथ से चली गई। कुल जमा चुनावों में वोट काटने की जिम्मेदारी बची, जिसकी धार भी अब भीथरी होती जा रही है। तीसरे भतीजे धनंजय मुंडे अपने चाचा के जिले बीड तक ही सीमित रह गए। उन्हें पारिवारिक मामलों से फुसंत नहीं मिल रही है। कभी चचेरी बहनों को चुनौती देते हैं तो कभी अपने निजी मामलों में ही उलझ कर रह जाते हैं। हालांकि राकांपा में उन्हें लाने वाले शरद पवार उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। सरकार बनने पर अवश्य ही उन्हें

मंत्री बना देते हैं। साथ ही उनकी कभी कमजोर नहीं होने देते हैं। हालांकि जब धनंजय मुंडे अपने चाचा गोपीनाथ मुंडे की भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) से अलग हुए थे तो यह अपेक्षा की जा रही थी, वह पार्टी का नुकसान करने में कुछ समर्थ होंगे। किंतु वह अपनी सत्ता की सीमा तक ही सिमट कर रह गए। यदि राजनीतिक ताकत को व्यक्तिगत स्तर तक भी देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में अजित पवार अपने पुत्र पार्थ को ही जिताने में असमर्थ रहे। पुणे जिले की कुछ सीटों को छोड़ कहीं भी अपने दम पर सीटें जीत कर लाने में वह कभी सक्षम नहीं पाए गए, जो साफ करता है कि उनकी गाड़ी अपने चाचा के साथ तालमेल और सहयोग से बढ़ती है। किंतु दोनों की ताकत की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में पचास का आंकड़ा पार कर पाती है। ऐसे में अजित पवार की चाचा के बगैर नैया कैसे पार लगेगी, यह समझना मुश्किल है। राज ठाकरे लगातार कभी खुद पर, कभी पार्टी पर प्रयोग करते जा रहे हैं। हालांकि पोस्टर, झंडा सब बदल कर भी कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। बीड जिले तक सीमित धनंजय मुंडे अपने कुनवे का नुकसान कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है, मगर मराठवाड़ा में अपनी ताकत का अहसास करा कर राकांपा को

एक नई ऊंचाई दे पाना उनके बस की बात नहीं है। पार्टी में आकांक्षा रखना और उसे पूरा करवा पाना अलग हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जाकर अपनी स्वतंत्र छवि बना पाना मुश्किल ही होता है। कुछ राजनीतिक सीमाओं का अनुमान होने के कारण ही अतीत में भी तीनों भतीजों की महत्वाकांक्षाओं को पंख लगने का अवसर नहीं मिला और भविष्य में भी यही स्थितियां बन रही हैं। बनी-बनाई पार्टी और विधायक दल को तोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन अपनी पार्टी और विधायक दल को खड़ा कर पाना इतना आसान नहीं होता, जितना वे भतीजे मानते हैं। इतिहास गवाह है कि राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा तीनों दलों से टूट के बाद उभरा कोई भी नेता बड़ा होकर सामने नहीं आ सका। सभी को किसी न किसी दल में शामिल होकर अपनी आकांक्षा-महत्वाकांक्षा को पूरा करना पड़ा। अवश्य ही महाराष्ट्र में पिछले कई दशक से किसी दल विशेष को बहुमत न मिलने से दूसरे दल के समर्थन-गठबंधन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में महत्वाकांक्षी नेताओं में उम्मीदें उड़ान भरने लगती हैं, किंतु उसमें क्षमता और संभावना को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे में एक बार की खुशी बार-बार की खुशियों में बदल नहीं पाती है। इन दिनों अजित पवार पूरी तरह से अपने तेवर दिखा रहे हैं। कभी यही स्थिति राज ठाकरे की थी। धनंजय मुंडे और समीर भुजबल दोनों को मजबूरियों ने समेट दिया है। आगे क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनाधार के बिना कोई भी कदम ज्यादा दिन चल नहीं पाता है। यह लोकतंत्र की सच्चाई है और जिसे उनके चाचाओं ने अपनी पार्टी को चलाने के दौरान अच्छे से समझा है। किंतु उनका दुर्भाग्य ही है कि वे इसे अपने भतीजों को समझा नहीं पाए हैं।

प्रसंग शिक्षा ताको दीजिए, जाकों सीख सोहाय

एक बार गुरु गोविंदसिंह के पास एक सीधा-सादा जाट आया और उसने उनसे देने को को उन्होंने उसे थोड़ों की सेवा करने के लिए कहा ज उसका नाम पूछा तो उसने बेला बताया। गुरु गोविंदसिंह ने आगे पूछा, क्या कुछ -वाह भाई बेला, न पहचाने लिखना पढ़ना आता है? जी नहीं, उसने जवाब दिया तब वे बोले, अच्छ म तुम्हें पढ़ाएंगे। आज से तुम इस वाक्य को रोज कहा करो. वन पहचाने बेला वह बेचारा इसे ही गुरु का मंत्र जान, रोज उसका जाप करने लगा। जब दूसरे शि ने उसे इस वाक्य की रट लगाते देखा, तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, आपने बेला को कैसा वाक्य रटने के लिए दिया है ? गुरुदेव ने जवाब दिया, जिसमें बेला यानी वल को नहीं पहचाना, उसने इस संसार में कुछ नहीं जाना। मगर जो बेला के महत्त्व को समझ पायेगा वह निश्चय ही पार हो जायेगा। बेला ने जब इसे सुना तो वह उस वाक्य को ज्यादा से ज्यादा दुहराने लगा। गुरुदेव उसकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे नित्य एकांत में उपदेश देने लगे। अन्य शिष्यों ने जब यह

देखा, तो उन्हें बेला से ईर्ष्या हुई। आखिर उनमें से एक ने एक दिन गोविंदसिंहजी से प्रश्न किया, गुरुदेव, क्षमा करें, हम लोग आपकी निःस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, लेकिन आप केवल इस निरक्षर बेला को ही उपदेश देते हैं। गोविंदसिंह ने उसके प्रश्न का जवाब न दे उससे कहा, एक घड़ा भर भंग पीसो और घड़ा खत्म होते तक सब लोग उसका कुल्ला करो। घड़ा खत्म हो जाने पर उन्होंने हर एक से पूछा, नशा चढ़ा या नहीं ? सबने उत्तर दिया, नहीं। जब उन्होंने बेला को बुलाया, तो सबने देखा कि उसे नशा चढ़ा है और नशे में भी वह वाह भाई बेला.... की रट लगाये हुए है। तब गुरुदेव उस शिष्य से बोले, क्या तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया ? बेला को भंग के साथ-साथ नाम का भी नशा चढ़ा है, क्योंकि उसने इन दोनों को दिल से ग्रहण किया है, जबकि तुम लोग कोई भी काम ऊपर ही ऊपर करते हो, दिल से नहीं। जान लो कि जब तक भगवान् के प्रति दिल से प्रेम न हो, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

- 1661 चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया।
- 1639 दिल्ली में लालकिले की नींव रखी गई।
- 1848 सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म।
- 1997 रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू।
- 1999 बच्चों के यौन शोषण पर रोक संबंधी विधेयक जापानी संसद में मंजूर।
- 2006 पाकिस्तान ने हल्क-6 का परीक्षण किया।
- 2007 ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्वकप जीता।
- 2008 ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद एक संक्षिप्त यात्रा पर भारत पहुँचे। तिब्बत में मार्च 2008 में भड़की हिंसा के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत ने 17 लोगों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

शाण्डिल्यापोनघट्ट (भाग-15)

गतांक से आगे...
यहाँ संयम का अर्थ अपने चित्त के माध्यम से स्थान विशेष में स्थित दिव्य चेतन धारा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना। तादात्म्य की स्थिति में उस चेतना विशेष के साथ जुड़े सारे तथ्य वित्त की अनुभूति में सहज ही आने लगते हैं। योगदर्शन में धारणा, ध्यान और समाधि की एकत्र स्थिति को संयम कहा जाता है। अब प्रत्याहार का वर्णन करते हैं। वह पाँच प्रकार का है। विषयों में विचरण करती हुई इन्द्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट करने (इन्द्रियाँ बाह्य भोगों में रस लेने की अभ्यस्त होती हैं, उन्हें बाह्य उपकरण में से हटाकर अन्तःकरण की रसानुभूति से जोड़ लेने) को प्रत्याहार कहा जाता है। जो-जो दिखाई देता है,



वह सब आत्मा हैं, ऐसा समझना चाहिए. (आँख, नाक, कान आदि विभिन्न अवयवों की अनुभूि वास्तव में आत्मा के ही कारण है। इसका बोध होना) यही प्रत्याहार है। नित्य किये गये कर्मों के फल का परित्याग (कर्म के फल में रस लेने की अपेक्षा कर्म करने में ही रस एवं सार्थकता की अनुभूति होने पर फल की कामना न रहना) ही प्रत्याहार है। समस्त प्रकार की विषय-वासनाओं से रहित होना (अन्तःस्थिति उच्च रसों की अनुभूति के आधार पर विषयों के रस को कामना न रहना), यह प्रत्याहार है। अद्भुतहर्म मंत्र स्थलों (आगे कहे गये) में क्रमशः धारणा करना (उन स्थानों पर स्थित चेतन दिव्य प्रवाहों के साथ चित्त का तादात्म्य स्थापित करके

कुष्ठ पीड़ितों की सेवा करने वाले दामोदर गणेश बापट

1962 में महाराष्ट्र के सदाशिव गोविंदराव कात्रे ने सोंटी के पास कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। कात्रे के साथ गणेश बापट ने कुष्ठ रोगियों के साथ-साथ उनके सामाजिक और वित्तीय पुनर्वास के लिए काम किया। उनके निधन के बाद 1972 से दामोदर गणेश बापट ने यहाँ का काम काज संभाला था। प्रदेश के अलावा देश के कोने-कोने से यहाँ कुष्ठ के मरीज भर्ती होते हैं। जिनकी सेवा के लिए दामोदर गणेश बापट ने अपनी पूरी उम्र खपा दी थी। 1975 में, बापट को भारतीय कुष्ठ निवारक संघ के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, और इसके बाद उनकी वृद्धि का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 1972 से लेकर 2019 में अपनी मृत्यु तक, अपने जीवन के अंतिम साढ़े चार दशकों के दौरान उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। उन्होंने कुष्ठ रोग के बारे में जन जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया।



वे लगातार 37 सालों से कुष्ठ पीड़ितों का इलाज करने पूरी लगन से काम करते रहे। उनके इस कार्य को देख 26 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। वे हमेशा कुष्ठ पीड़ितों की सेवा में ही लीन थे। बापट आश्रम के एक कमरे में केवल एक बिस्तर और दो सादे कपड़ों में पूरी जिंदगी बिता दी। आश्रम में करोड़ों की संपत्ति उनके नाम है। चाहते तो वे

सर्वसुविधायुक्त एसी कमरे रह सकते थे, लेकिन वे दो सादे कपड़े में ही पूरी जिंदगी बिता दी। बापट ने आश्रम न केवल एक सर्वसुविधायुक्त अस्पताल का निर्माण कराया बल्कि आश्रम के साथ-साथ सुशील बालक गृह का भी निर्माण कराया। जहाँ अनाथ व गरीब बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। आश्रम में सैकड़ों छात्र पिछले तीन दशक से निवासरत हैं। बचपन से ही उनके मन में सेवा की भावना कूट-कूटकर भरी थी। यही वजह है कि वे करीब 9 वर्ष को

आयु से आरएसएस (राष्ट्रीय सेवा संघ) के कार्यकर्ता बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद बापट ने पहले कई स्थानों में नौकरी की, लेकिन उनका मन नहीं लगा। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ के वनवासी कल्याण आश्रम जशपुरनगर पहुँचे और बच्चों को पढ़ाने लगे। पढ़ाने के दौरान वे कुष्ठ रोगियों से भी मिले और जीवन भर उनकी सेवा करते रहे। **पुरस्कार**

12 सितंबर 2006 को, उन्हें श्री अहिल्यात्वस्व समिति, इंदौर द्वारा 10वें राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास, शिक्षा और सुधार में उनकी सेवा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। 2018 में में उन्हें कुष्ठ रोगियों के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले गणेश बापट को पद्मश्री सम्मान से नवाज गया था। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार से भी सम्मानित किया गया था। बापट ने अन्य पुरस्कारों को भी प्राप्त किया, जैसे विवेकानंद सेवा पुरस्कार, श्री बडवाबाजार कुमार सभा पुस्ताकालया, कोलकाता द्वारा प्रदान किया गया; भाऊराव देवरास फाउंडेशन द्वारा भाऊराव देवरास सेवा स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है ड्रेगन

हर्ष वी. पंत

अमेरिका-चीन संघर्ष का एक नया मोर्चा हाल ही में तब खुला, जब सन्नद्ध ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर न्यू यॉर्क के मैनहटन के चाइनाटाउन इलाके में गुप्त तौर पर चीनी 'पुलिस स्टेशन' चलाने का आरोप था। पिछले महीने ही कनाडा ने भी कुछ जगहों पर जांच शुरू की थी, जहाँ से कथित तौर पर ऐसी ही गतिविधियाँ चलाई जा रही थीं। हालांकि, चीन ने ऐसे आरोपों से हमेशा इनकार किया है, लेकिन खबरें हैं कि 50 से अधिक देशों में ऐसे करीब 100 कथित पुलिस स्टेशन हैं, जो विदेश में रहने वाले चीनी राष्ट्रीयता के लोगों पर नजर रखते हैं। चीन इन्हें ऐसे सर्विस सेंटर के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, जिनका मकसद चीनी राष्ट्रीयता के लोगों की सहायता करना है, लेकिन वास्तव में यह चीनी राज्य तंत्र की ओर से विदेशी जमीन पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास है। यह चीन में बढ़ते इस विश्वास का प्रतीक है कि वह बिना रोक-टोक के अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रख सकता है। मैनहटन में यह गिरफ्तारी ऐसे वक हुई, जब चीन अपनी एक सौम्य राष्ट्र की छवि बना रहा है। ऐसे राष्ट्र की, जो वैश्विक समस्याओं को हल करने और झगड़ों को निपटाने में लगा हुआ है। बरसों से अपने संशोधनवादी अजेंडे पर दुनिया भर के देशों की लानत-मलामत झेलते पेइचिंग को इस बात का अच्छी तरह अहसास हो चुका है कि उसे अपनी सॉफ्ट छवि पेश करने की जरूरत है। जब तमाम वैश्विक नेता कोविड बाद के दौर में चीन से संपर्क में आए तो उसके लिए संभावनाओं की एक नई



खिड़की खुली। वह अब नए ढंग से अपनी मौजूदगी महसूस करा सकता था। पिछले कुछ महीने चीन के लिए कूटनीतिक तौर पर असामान्य रूप से व्यस्त रहे। उसने कई नेताओं की मेजबानी की, यूरोप और मध्यपूर्व के क्षेत्रों तक पहुंचा। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध और सऊदी अरब-ईरान विवाद में उसने खुद को शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में पेश किया। 'बुल्क वॉरियर' डिप्लोमेसी की जगह उसका ज्यादा संतुलित रख नजर आने लगा। चीन ने दुनिया भर में लोगों को प्रभाव में लेने और दोस्त बनाने की कोशिश शुरू की। वैश्विक पटल पर खुद की नई छवि गढ़ने की इन कोशिशों के पीछे कहीं न कहीं चीन की यह इच्छा काम कर रही थी कि उसे अमेरिका के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देखा जाए। सोच यह है कि अगर अमेरिका आंतरिक कारणों से मजबूर दिख रहा है और वैश्विक मामलों में उसकी उदासीनता से जो शून्य पैदा हो रहा है, उसे भरने में चीन को देर नहीं करनी चाहिए। जहाँ कोविड के दौरान चीन अपनी घरेलू परेशानियों में उलझा नजर

आ रहा था, वहीं कोविड के बाद के दौर में अपेक्षा यह होगी कि चीन वैश्विक पटल पर समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता दिखे। यह ऐसा दौर है, जब विश्व व्यवस्था में भी नेतृत्व के स्तर पर एक शून्य दिख रहा है। बड़ी ताकतों के रिश्तों में दरार आ गई। वहीं, दुनिया भर में भू-राजनीतिक बदलाव तेज हुए हैं। दूसरी ओर, भू-आर्थिक संकट भी दिख रहे हैं। ऐसे में चीन खुद को एक भरोसेमंद वैश्विक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि अगर उसने तेजी नहीं दिखाई तो भारत जैसे देश और मोदी जैसे नेता इस भूमिका में आगे निकल सकते हैं। कोविड के दौरान विकासशील देशों की मदद में तत्पर रहकर और 'ग्लोबल साउथ' को जी-20 अध्यक्षता के केंद्र में बनाए रखकर भारत ने असल में चीन की विकासशील देशों के नेता की स्वनिर्मित छवि को चुनौती दे दी है। वैसे शी चिनफिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भी इस सचाई का अहसास हो रहा है कि पिछले करीब एक दशक में अपनाई गई बेहद आक्रामक विदेश नीति ने उसे काफी हद तक अलग-थलग कर दिया है। अब जब चीन कोविड से उपजी आर्थिक सुस्ती से उबर रहा है तो उसे पश्चिम की मदद चाहिए। पश्चिमी मदद के बगैर चीनी अर्थव्यवस्था रफ्तार नहीं पकड़ सकती। शानद इसीलिए जीरो कोविड पॉलिसी के खत्म होने के बाद चीन ने सबसे पहले यूरोप का रुख किया। फरवरी में वांग यी यूरोप गए। मकसद चीन-यूरोप रिश्तों की तस्दीक करना था और यूरोप को अमेरिका से दूर करने की संभावनाएं खंगालना भी। यूक्रेन पर किसी स्पष्ट योजना के बगैर उस दिशा

में बात नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए चीन ने दो पोजिशन पेपर जारी किए। एक शांति प्रस्ताव यूक्रेन युद्ध के लिए और दूसरा पूरी दुनिया के लिए, जिसमें संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और इकतरफा पाबंदियाँ लगाने से बचने की बात केंद्र में थी। शी चिनफिंग के मॉस्को दौर में रूस-चीन की नजदीकी पर जिस तरह से जोर दिया गया, उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि यूक्रेन शांति योजना का यूक्रेन से शायद ही कोई मतलब था। इसका मकसद यह रेखांकित करना था कि जहाँ अमेरिका युद्ध को अधिक से अधिक लंबा खींचने में लगा है, वहीं चीन एक ऐसा देश है जो इस संकट को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। यह संदेश दुनिया के उस बड़े हिस्से के लिए था, जो यूरोप में लड़े जा रहे इस युद्ध की कीमत चुकाते-चुकाते थक चुका है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद चाहे ताइवान में सैन्य धमकियों की बात हो या ईस्ट और साउथ चाइना सी के विवादों में आक्रामक रवैया जारी रखने की, यह स्पष्ट है कि अपनी मुख्य मांगों को लेकर झुकने का चीन का कोई इरादा नहीं है। भारत-चीन सीमा का मसला भी बना ही रहने वाला है ताकि भारत पर दबाव कायम रहे। कुल मिलाकर, चीन की कूटनीतिक शब्दावली में इन दिनों भले कुछ बदलाव दिख रहा हो, उसके कार्य उसी पुरानी दिख को मजबूती दे रहे हैं जिसके मुताबिक यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी भी कीमत पर अपनी जगह बनाना चाहता है। ऐसे में नई छवि बनाने की उसकी ताजा कवायद को बाकी दुनिया कितनी अहमियत देती है, यह देखने वाली बात होगी।

बापू की दिनचर्या

निद्रा - त्याग



बापू की दिनचर्या ब्राम्हमुहूर्त से प्रारंभ हो जाती। भारत जैसे समशीतोष्ण दे में सभी के लिए सूर्योदय से पहले निद्रा-त्याग वे आवश्यक मानते। उनक दृष्टि में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं। हॉ, इसके विपरीत आचरण करने पर उन्हें आश्चर्य जरूर होता, क्योंकि कृषिप्रधान भारत के किसान यदि दे तक शयनसुख लेते रहें, निद्रा-मग्न रहें, तो उनके पशुओं के आहार तथ उनकी खेती का काम तग हो जाए। जोहार्नवर्म (दक्षिण अफ्रीका) पहुँचने तक बापू स्वयं सुबह छह-सात बजे से पहले प्रायः सोकर नहीं उठ पाते, किंतु इसके बाद आधी रात में सोने पर भी आम तौर पर धोर में साढ़े तीन बजे उठ जाते। आम तौर पर उनके उठने का समय चार बजे था। जब वे विशेष कार्यरत रहते, तब अपनी नींद और अपने कष्ट का खयाल किए बिना निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने की चेष्टा करते। ऐसे कुछ प्रसंग उल्लेखनीय हैं। बापू जून, सन् 1934 में काशी विद्यापीठ में कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक के अवसर पर पधारे। उस समय वे कुछ अस्वस्थ थे, फिर भी अपने सहायकों को आधी रात में उठाकर कार्य में जुट जाते। बापू के सचिव इस विषय में उनसे आगे रहते। सेवा का कोई अवसर वे हाथ से जाने नहीं देते। सेवाग्राम में भी बापू रात में दो-तीन बजे उठकर लिखते। इसे काका साहब ने ९%नींद पर अत्याचार की संज्ञा दी। बापू यद्यपि स्वयं इससे सुपरिचित थे। और निद्रा पूर्ण मात्रा में लेने को कहते; तथापि कभी-कभी परिस्थितिवशा ऐसा करना उनके लिए कठिन हो जाता। उसको सो तो फिर लेंगे, लेकिन किसी कार्य का समय नियत होता है और पूर्ति समय से होनी ही चाहिए। निद्रा बापू की चौ थी। उनकी नींद ऐसी सभी भी कि अलमर्न के बिना वे उन बैठते, फिर भी कभी-कभी लगाते। एक बार उन्होंने रात में तीन बजे का अला लगाया, किंतु अलामे बाह्र बजे से पूर्व ही बज गया। वे उठ बैठे। उन्होंने दातून को भी लिखने बैठ गए। कुछ देर बाद घड़ी पर नजर पड़ी तो बारह का समय था। कार्यभार अबस्था पुनः सोने का साहस न कर सकें और लिखते रहे। एक बार एक प उन्होंने रात ढाई बजे लिखा था। एक बार वे रात में एक बजे बिलकुल ताजगी की हालत में उन बैठे। उन दिनों उनके उनके का यह सामान्य बन गया। इस आंतरिक प्रेरणा को वे ईश्वर की देन मानते।

संक्षिप्त समाचार

आईएएस आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

रायपुर। प्रदेश के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्डिंग और शराब घोटाला मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम अनिल टुटेजा को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पिता और बेटे की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएसानुद्दीन अमनउल्लाह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत बताया था। याचिका में कहा गया कि मनी लॉन्डिंग के मामले को ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि याचिकाकर्ताओं ने कैसे अवैध तरीके से धन जमा किया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ईडी की नियमावली में इन बातों को बताया हुए ही कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है। जिसका ईडी द्वारा पालन नहीं किया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टुटेजा के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन तब तक ईडी टुटेजा के खिलाफ किसी भी तरह की सख्ती नहीं कर पाएगी।

आप के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण आज

रायपुर। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने हाल ही में प्रदेश की नई कार्यकारिणी गठित की है। 29 अप्रैल को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक नए पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष कामल हुपंडी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक होंगे। इनके अलावा प्रदेश प्रभारी संजीव झा समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। समारोह में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को डॉ. संदीप पाठक शपथ दिलाएंगे। नवनियुक्त पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प भी दिलाएंगे। कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और उमंग भरते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे।

रेलवे स्टेशन के होटल में लगी भीषण आग, तेज आवाज के साथ हुआ धमाका

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक निजी होटल में बीती रात को भीषण आग लग गई। आग लगने पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोग चीख पुकार करने लगे। यह आग होटल के सामने के हिस्से में लगी थी। जिस होटल में आग लगा उस होटल में लोग मौजूद थे। उन्हें होटल से बाहर निकाला गया। इस दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। आग लगने के दौरान धमाके की आवाज सुनकर लोग काफी भयभीत हो गए थे। मामले में जीआरपी थाना प्रभारी जीएस राजपूत ने बताया कि यह घटना बीती रात गुरुवार की है। होटल में काफी लोग मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिससे कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया।

छत्तीसगढ़ में नहीं धम रखा कोरोना, 24 घंटे में 397 मरीज मिले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 397 कोरोना मरीज मिले हैं। कल 5296 सैम्पलों की जांच हुई, जिसमें 397 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बालोद जिले में दो और कोडगांव में एक मरीज की मौत हुई है। आज 584 लोग ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा बलौदाबाजार में 66 मरीज मिले हैं। इसके अलावा रायपुर में 37, दुर्ग में 21, राजनांदगांव में 23, बालोद में 15, बेमेतरा में 15, कबीरधाम में 5, धमतरी में 20, 36, महासमुंद में 8, बिलासपुर में 33, सरगुजा में 29, कांकेर में 21, बीजापुर में 8 संक्रमित मिले हैं।

एशियन पेरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए श्रीमंत झा का हुआ चयन

रायपुर। यू.ए.ई में पी.आई.यू.एफ कैटेगरी के 80 किलोग्राम कैटेगरी में 28 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित होने वाली एशियन पेरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई के पैरा एथलीट श्रीमंत झा का चयन हुआ है। पैरालंपिक श्रीमंत अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश का मान बढ़ाएंगे। झा स्कूल स्तर पर फुटबॉल खेलना चाहते थे लेकिन उनके दाहिने हाथ के काम न करने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। फिर उन्होंने पास के एक जिम में दाखिला लिया और पैरा-कुश्ती सीखी और अभ्यास करना शुरू किया। गौरतलब है कि श्रीमंत झा इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। पैरालंपिक खिलाड़ी श्रीमंत झा वर्तमान में एशिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं और विश्व के नंबर तीन खिलाड़ी हैं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में श्रीमंत झा देश के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं।

मुख्यमंत्री ने किया निर्माण कार्य का लोकार्पण-शिलान्यास

कुरुद विधानसभा के सेमरा बी. में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम

धमतरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कुरुद विधानसभा के प्रवास के दौरान सेमरा बी. में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में कुल 82 करोड़ 39 लाख 05 हजार रुपये के 65 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 45 करोड़ 27 लाख 15 हजार रुपये के 31 कार्यों का लोकार्पण और 37 करोड़ 11 लाख 90 हजार रुपये के 34 कार्यों का शिलान्यास शामिल है।

उन्होंने उद्यानिकी विभाग के 9.40 लाख रुपये की लागत के दो कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें कुरुद के शासकीय उद्यान रोपणी गाड़डीह में चार लाख रुपये की लागत के कर्मचारी आवास निर्माण और 5.40 लाख रुपये की लागत के वर्किंग शेड निर्माण शामिल है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी के 106.12 लाख रुपये की लागत के दो कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें गातापार स्थित दुग्ध प्रोसेसिंग इकाई हेतु 35 लाख रुपये की लागत से शेड निर्माण और भखारा में 71.12 लाख रुपये की लागत का नवीन तहसील कार्यालय भवन निर्माण सम्मिलित है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 201.55 लाख रुपये की लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। इनमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमर, मरीद, थूहा और मंदरीद में 6.83-6.83 लाख रुपये की लागत के प्रयोगशाला कक्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमर में कला एवं सांस्कृतिक कक्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थूहा, मंदरीद और संकरी में कम्प्यूटर कक्ष निर्माण 6.34-6.34 लाख रुपये की लागत का लोकार्पण किया। इसी तरह 8.34-8.34



लाख रुपये की लागत के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमर और मरीद में पुस्तकालय कक्ष निर्माण का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया। ग्राम पंचायत भेंडसर में 13.65 लाख रुपये की लागत से सी.सी.रोड निर्माण, ग्राम पंचायत बगदेही में 4 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण, 7.94 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण का लोकार्पण किया। ग्राम धूमा में 5.90 लाख रुपये की लागत से बाजार शेड निर्माण और जनपद पंचायत कुरुद के तहत 100.70 लाख रुपये की लागत के 16 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से कुल 486.74 लाख रुपये के सात रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना के तहत कार्य कराए जाएंगे। इनमें भाटागांव रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना 72.06 लाख रुपये, गातापार अ. में 59.97 लाख रुपये, देवरी में 48.83 लाख रुपये, दहदहा में 49.97 लाख रुपये, गोजी में 63.06 लाख रुपये, कमरीद में 96.76 लाख रुपये और मौरीकला में 96.90 लाख रुपये की लागत के चरलू नल

कनेक्शनों में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया। सीजीएमएससी लिमिटेड संभाग रायपुर की ओर से कुरुद के भखारा में 27.26 लाख रुपये की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया। लोक निर्माण विभाग सेतु की ओर से बड़ी करेली-नारी मार्ग में 3654.27 लाख रुपये की लागत से महानदी पर उच्च स्तरीय पुल और वाणिज्यिक कर विभाग जिला पंजीयक धमतरी की ओर से 41.81 लाख रुपये की लागत से उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण कुरुद का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा 37 करोड़ 11 लाख 90 हजार रुपये के 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 188.23 लाख रुपये की लागत से 22 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें उच्च प्राथमिक शाला सिराँ और सिवनीकला में 15.08 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष निर्माण का शिलान्यास किया। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बगौद में 9 लाख

रुपये की लागत से पुस्तकालय कक्ष निर्माण, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भैंसबोड़ में 6.96 लाख रुपये की लागत से कला एवं सांस्कृतिक कक्ष निर्माण, संकरी, मौरीखुर्द दहदहा में 3-3 लाख रुपये की लागत से रंगमंच निर्माण, ग्राम पंचायत करगा में सीसी रोड, धूमा में शेड निर्माण, ग्राम पंचायत बंगोली में नाली निर्माण, नवागांव में पक्की नाली, सुपेला और कुराँ में आरसीसी नाली निर्माण, प्रत्येक कार्य 3-3 लाख रुपये की लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत करगा में 4 लाख रुपये की लागत की आरसीसी नाली निर्माण, ग्राम पंचायत चरमुंडिया में 3.40 लाख रुपये की लागत का बोर खनन एवं सोलर पंप फिटिंग, ग्राम पंचायत चारभाठा में 4.79 लाख रुपये की लागत का मुक्तिधाम सह प्रतीक्षालय निर्माण का शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत गातापार आ में 5.01 लाख रुपये की लागत का नाली निर्माण, सिर्वें में 3.97 लाख रुपये की लागत से अहाता निर्माण कार्य और किचन शेड निर्माण कार्य तथा ग्राम चर्रा में 3.40 लाख रुपये की लागत से दंतेश्वरी मंदिर के सामने सीसी करण कार्य का शिलान्यास किया। ग्राम मोंगरा में 6 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण, ग्राम भैंसबोड़ में 3.50 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण, ग्राम दहदहा में 5 लाख रुपये की लागत का पूर्व माध्यमिक कन्या शाला प्रांगण में स्वच्छता सह सीसी करण कार्य का शिलान्यास किया। जनपद पंचायत कुरुद के तहत 94.12 लाख रुपये की लागत के 21 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

लोक निर्माण विभाग की ओर से 3493.19 लाख रुपये की लागत के कुल

11 कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा किया। इनमें 465.84 लाख रुपये की लागत से शासकीय नवीन महाविद्यालय सिलौटी, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद में 64.87 लाख रुपये की लागत से साईंस लेबोरेटरी भवन उन्नयन, आदर्श पुस्तकाल भवन उन्नयन कार्य का शिलान्यास शामिल है। इसी तरह खैरा से मोंगरा तक 165.55 लाख रुपये की लागत से 2.50 कि.मी. मार्ग निर्माण, नवागांव (थूहा) से सोनपुर तक 106.76 लाख रुपये की लागत से 1.50 कि.मी. मार्ग निर्माण और 1552.50 लाख रुपये की लागत से सिराँ-फुसेरा-करगा-चटौद मुख्य जिला मार्ग 9.30 कि.मी. का चौड़ीकरण का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

कल्ले-अंवरी-सेमरा-आमदी-धमतरी मुख्य जिला मार्ग से सेमरा खारून पुल हाई लेवल ब्रिज तक 208.49 लाख रुपये की लागत से 1.20 कि.मी. लंबी मार्ग, कोडेबोड़ से अछोटी नहर नाली पहुंच मार्ग लंबाई एक कि.मी. 95.72 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। भाटागांव-भखारा-रामपुर तक 4.50 कि.मी. मार्ग का 325.68 लाख रुपये की लागत से मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसी तरह सिराँ-खर्रां-दर्रां-पटेवा 5.80 कि.मी. मार्ग 507.78 लाख रुपये की लागत से चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। साथ ही सीजीएमएससी लिमिटेड संभाग रायपुर की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरुद में 30.48 लाख रुपये की लागत से 20 बिस्तरयुक्त अतिरिक्त वार्ड का निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया।

पॉवर कंपनी के मुख्य अभियंता की भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के मुख्य अभियंता (सी.पी.एंड बी.डी.) श्री रामजी सिंह को सेवानिवृत्त उपरान्त कंपनी मुख्यालय विद्युत सेवाभवन में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी श्री एस.के.कटियार एवं निदेशक(कार्मिक प्रशासन) श्री के.एस.रामाकृष्णा ने उन्हें प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशकों ने सेवानिवृत्त श्री सिंह की सेवाओं को प्रदेश के



विद्युत विकास के लिए महत्वपूर्ण निरूपित करते हुए उनके द्वारा विद्युत मंडल एवं कंपनी में दिये गये योगदान की सराहना की तथा उनके उज्वल एवं सुखमय भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त

श्री सिंह ने अपने कार्य अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उनका लंबा समय संयंत्र की जिम्मेदारी संभालते हुए बीता। उन्हें मुख्यालय में भी काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय टीमवर्क को दिया।

इसके अतिरिक्त पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग में पदस्थ अधीक्षण अभियंता श्री संजय जैन एवं अनुभाष अधिकारी श्री रामेश्वर नागतोडे को भी संबोधित

कार्यालयों में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन) श्री के.एस.रामाकृष्णा, मुख्य अभियंता(मानव संसाधन) श्री अशोक कुमार वर्मा, चीफ सिन्डिकेयोरिटी ऑफिसर विंग कमांडर ए.श्रीनिवास राव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री एच.एल.पंचारी, उपमहाप्रबंधक श्रीमती अल्पना शरत तिवारी एवं संचालन प्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविंद पटेल एवं सहायक प्रकाशन अधिकारी श्रीमती अनामिका मंडावी ने किया।

शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने किया चक्काजाम

प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

कांकेर। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने आज कांकेर में चक्काजाम किया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत व अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में महिला कार्यकर्ता सड़क पर बैठी रहीं। लगभग आधे सड़क जाम कर बैठी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जामकर नारेबाजी की।



कहना है कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराब बंदी लाने की बात कही थी। पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है अब तक शराब बंदी नहीं लागू की गई। शराब की वजह से प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो सका।

दो महीने पहले गहराई में आईडी लगाये जाने की संभावना - सुदरराज पी

शहीद जवानों में से 05 जवान आत्मसमर्पण करने के पश्चात डीआरजी में कार्यरत थे

जगदलपुर। बस्तर आईजी सुदरराज पी ने नक्सल घटना के संदर्भ में अद्यतन जानकारी देते हुए बताया कि दत्तेवाड़ा जिले के अरनपुर घटना स्थल के निरीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया यह प्रतिष्ठ हो रहा है कि नक्सलियों द्वारा आईडी की लगभग डेढ़ से दो महीने पहले सड़क के किनारे से सुरंग खोदकर लगाया गया जिसके तार को सड़क के किनारे घने जंगल से आड़ लेकर जमीन के नीचे लगभग 2-3 इंच दबाकर लगभग 150 मीटर दूर तक ले जाकर मौका देख कर 26 अप्रैल 2023 को विस्फोट की वारदात को अंजाम दिया गया। उक्त मार्ग में समय-समय पर डी-माईनिंग की कार्यवाही की जाती है ऐसे प्रतीत होता है कि उक्त आईडी सुरंग खोद कर सड़क के काफी नीचे लगाई गई थी जिसके कारण डी-माईनिंग के दौरान इसे पकड़ा नहीं गया, जांच उपरांत अतिरिक्त जानकारी प्रदाय की जायेगी। शहीद जवानों में से 05 जवान क्रमशः प्र.74 जोगा सोदी, प्र.आर.965 मुशा राम कड़ती, नव आर.888 हरिाराम मण्डवी, नव आर. 580 जोगा कवासी, गोपनीय सैनिक राजू राम कट्टम शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने के पश्चात पुलिस विभाग डीआरजी में कार्यरत थे।



दरम्यानी रात नक्सल अभियान पर रवाना हुआ था। 26 अप्रैल 2023 के प्रातः लगभग 06.30 बजे पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। घटना स्थल का सर्चिंग करने पर 02 संदिग्ध नक्सली 01. मिलिशिया सदस्य लखमा कवासी पिता गंगा कवासी उम्र 30 वर्ष साकिन पोरोककाड़ी थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा 02. मिलिशिया सदस्य सन्ना उर्फ कोसा माडवी पिता हुंगा

डीआरजी दत्तेवाड़ा एवं सीएफ कैम्प नहाड़ी का संयुक्त बल थाना अरनपुर क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति होने की आसूचना पर 25 अप्रैल 2023 की

माडवी उम्र 25 वर्ष साकिन पोरोककाड़ी थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा को गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल से पिड्डू, नक्सल साहित्य, दैनिक उपयोगी समाग्री आदि प्राप्त हुई। जिस पर थाना अरनपुर में अपराध क्रमांक 04/2023 धारा 147,148,149,307 भादवि. 25,27 आर्म्स एक्ट 13(1), 38(2), 39(2) यूएपीए एक्ट के तहत दरभा डिवीजन कमेटी के नक्सली कैडर जगदीश, लखवे, लिंगे, सोमडू, महेश, हिड्डम, उमेश, देवे, नंद कुमार, लखमा, कोसा, मुकेश तथा अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मुठभेड़ में घायल नक्सली कोसा उर्फ सन्ना के जांच व हाथ की कोहनी में गोली लगी थी, जिसे तत्काल उपचार की आवश्यकता थी, जिसे उपचार हेतु डीआरजी की एक टीम जिला मुख्यालय लेकर आ रही थी, डीआरजी टीम 03 गाडियों में थाना अरनपुर से रवाना हुई थी नक्सलियों द्वारा पूर्व से घात लगाकर डीआरजी टीम की एक गाड़ी को थाना अरनपुर से 02 कि.मी. पूर्व पेडुका चौक पर आईडी ब्लास्ट किया गया एवं फायरिंग की गई जिस पर अपराध क्रमांक 05/2023 धारा 147,148,149,307,302 भादवि. 4.5 वि.प.अधि.नियम

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन रायपुर में

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 47.12 करोड़ रूपए की राशि श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित करेंगे

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 01 मई के अवसर पर राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में दोपहर 12 बजे से श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के अध्यक्षता श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल लगभग एक लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 47.12 करोड़ रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे और आरंग और पाटन में श्रमिक सहायता केन्द्र का शुभारंभ भी करेंगे।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी. एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताप्रध्वज साहू, संसदीय कार्य एवं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास तथा समाज

कल्याण मंत्री मती अनिला भेंडिया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, आवास एवं पर्यावरण तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भागत, सहित सांसद सुनील सोनी शामिल होंगे। इनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रेखचंद जैन, छत्तीसगढ़ राज्य हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, विधायकगण सत्यनारायण शर्मा, बुजमोहन अग्रवाल, महापौर रायपुर एजाज डेबर, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निगम कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सत्री अग्रवाल एवं सदस्यगण, छत्तीसगढ़ असांगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के सदस्यगण, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष शर्मा अहमद, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख एवं समस्त सदस्यगण उपस्थित रहेंगे।

कल्याण मंत्री मती अनिला भेंडिया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, आवास एवं पर्यावरण तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भागत, सहित सांसद सुनील सोनी शामिल होंगे। इनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रेखचंद जैन, छत्तीसगढ़ राज्य हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, विधायकगण सत्यनारायण शर्मा, बुजमोहन अग्रवाल, महापौर रायपुर एजाज डेबर, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निगम कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सत्री अग्रवाल एवं सदस्यगण, छत्तीसगढ़ असांगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के सदस्यगण, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष शर्मा अहमद, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख एवं समस्त सदस्यगण उपस्थित रहेंगे।

बाबूदी विस्फोट की घटना में 10 डीआरजी जवान क्रमशः 01. प्र.आर.74 जोगा सोदी, 02. प्र.आर.965 मुशा राम कड़ती, 03. प्र.आर.901 संतोष तामो, 04. नव आर. 542 दुलुगो मण्डावी, 05. नव आर. 289 लखमू मरकाम, 06. नव आर. 580 जोगा कवासी, 07. नव आर.888 हरिाराम मण्डवी, 08. गोपनीय सैनिक राजू राम कट्टम, 09. गोपनीय सैनिक जयराम पोडियाम, 10. गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी एवं 01 वाहन चालक धनीराम यादव शहीद हो गये। शहीद हुये समस्त डीआरजी जवान एवं वाहन चालक को विभागीय प्रावधान तथा शासन की नक्सल पीड़ित पुनर्वास निगम के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति, आर्थिक सहायता एवं समस्त सुविधाएं आगामी दिनों में त्वरित उपलब्ध करायी जायेगी। घटना के पश्चात् आस-पास के क्षेत्रों में लगातार पुलिस एवं सीआरपीएफ बल द्वारा सर्चिंग अभियान जारी है।

